वर्ष: 1 अंक: 21

1-15 मई 2021 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

उज्ज्वल होता देश उज्ज्वला

धुआं मुक्त रसोई से नए भारत के बदलाव की कहानी

संकल्प से सिद्धि...

इस बार नए कलेवर में आपकी "एग्जाम वारियर्स"

अलीना तायंगः मैं रोइंग, अरुणाचल प्रदेश की छात्रा हूं। मेरी परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एग्जाम वॉरियर्स किताब पढ़ी क्या? मैंने यह किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब इसे खरीदा तो 2-3 बार पढ़ गई। मुझे लगा कि ये किताब परीक्षा से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाभ होता। मैंने ये भी देखा कि इसमें छात्रों के लिए बहुत मंत्र है, लेकिन माता-पिता और शिक्षकों के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए संस्करण के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें माता-पिता, शिक्षकों के लिए कुछ मंत्र और विषय जरुर शामिल करें।

प्रधानमंत्रीः मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बताएंगे तो हो ही जाएगा। मेरे इस नन्हे से मित्र ने मुझे काम भी सौंप दिया है, कुछ करने का आदेश दिया है। मैं जरुर आपके आदेश का पालन करूंगा।

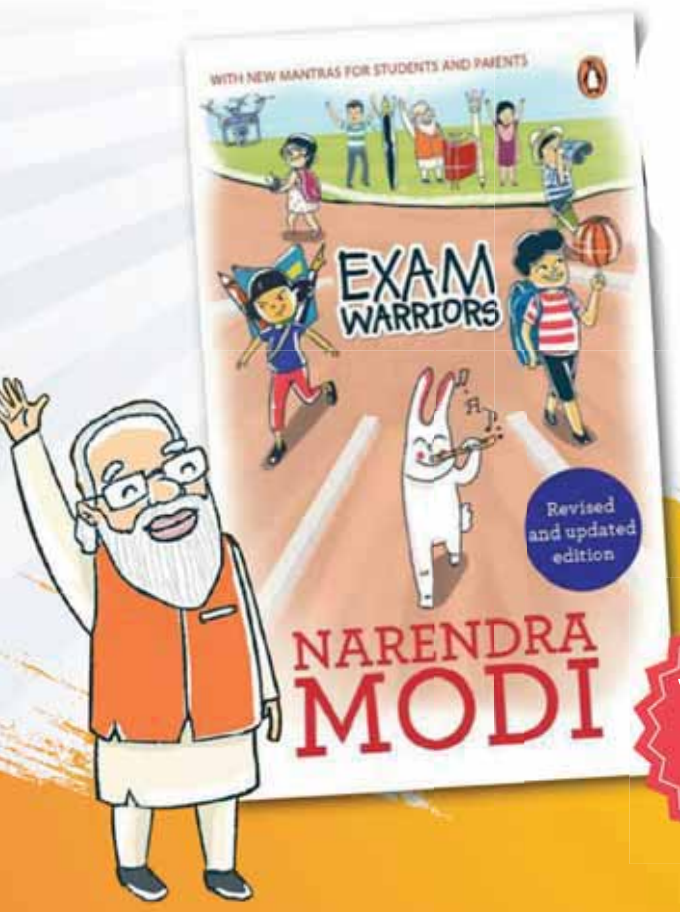

ऐसे एक छात्रा के आग्रह को पूरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, "Exam Warriors" पुस्तक के नए संस्करण में छात्रों के अलावा माता-पिता और शिक्षकों के लिए कुछ रोचक मंत्र जोड़े गए हैं ताकि छात्र तनाव मुक्त होकर एक मुस्कान के साथ परीक्षा में हों शामिल

अपनी प्रति आज ही मंगवाएं

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-Warriors-Revised-Updated-Narendra/dp/0143449974/ref=asc_df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&linkCode=df0&hvadid=396986125419&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11787528220984750938&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 21 |1-15 मई 2021

संपादक
जयदीप भटनागर,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

देश का भविष्य उज्ज्वल

आवरण कथा

ईज ऑफ लिविंग का सबसे उम्दा उदाहरण बनी उज्ज्वला योजना। 2014 तक 55% थी देश में रसोई गैस वाले परिवारों को संख्या, अब 99.6 फीसदी। पेज 18-27

फ्लैगशिप योजना...

जन सुरक्षा से जीवन रक्षा

पेज 32-33

जीवन को गढ़ने का अवसर है परीक्षा

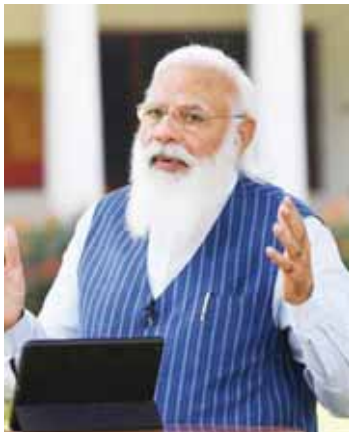

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाले मंत्र।

पेज 14-16

समाचार-सार
देश की प्रमुख खबरें | पेज 4-5

गोखले: जिन्हें खुद बापू ने महात्मा कहा
गोपाल कृष्ण गोखले जयंती पर विशेष | पेज 6

राष्ट्रनीति : आत्मनिर्भर भारत की पटकथा
आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक साल | पेज 7-9

कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई
खतरनाक हुए हालात, केंद्र सरकार ने कसी कमर | पेज 10-11

भीमा ने दी अंग्रेजों को चुनौती, झलकारी पर था झांसी को नाज
अमृत महोत्सव में इस बार 1857 के दो क्रांतिकारियों की कहानी | पेज 12-13

1 करोड़ रोजगार के अवसर की दिशा में कदम
कैबिनेट के फैसले | पेज 17

पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संपूर्ण विकास संभव
उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण महताब की पुस्तक का विमोचन | पेज 28-29

परंपरा को मिली पहचान, हुनरमंद हाथ को हौसला
उस्ताद योजना के जरिए बना रहे हाथों को हुनरमंद | पेज 34

महापराक्रमी महाराणा
मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप के पराक्रम को नमन | पेज 35

पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता
कहानी बदलते भारत की | पेज 36

पोखरण: जब दुनिया ने देखी भारत की शक्ति

23 साल पहले जब दुनिया ने देखी हमारी ताकत...ऑपरेशन शक्ति के जरिए भारत को परमाणु सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की कहानी। पेज 30-31

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले साल देश ने एकजुटता के साथ कोरोना को हराया था। भारत एक बार फिर से तेज गति और समन्वय के साथ कोरोना को उसी तरह से हराएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर कोरोना से लड़ने की दवाई दी है, लेकिन जब तक कोरोना से पूरी तरह हम मुक्त नहीं होते, तब तक हमें मास्क लगाने और सामाजिक दूरी जैसी सावधानी भी बरतनी है। देश का नेतृत्व इस जंग में बेहद संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रहा है और हर तरह की दवाईयों-अस्पतालों की जरुरत को सुनिश्चित किया जा रहा है, इसलिए घबराएं नहीं क्योंकि बचाव ही इसका कारगर तरीका है।

कोरोना के खिलाफ जंग हो या देश में योजनाओं के जरिए बदलाव लाना, जन भागीदारी ने हमेशा देश को नई दिशा दी है। इसी का परिणाम है कि आजादी के कई दशकों तक रसोई गैस की सुविधा जो सिर्फ एक खास वर्ग तक सीमित थी, उसका विस्तार गांव-गरीब तक हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने आम जन के जीवन स्तर से लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी मिसाल पेश की है, जिसकी आज दुनिया भी मुरीद है। इस योजना के छह साल पूरे हो रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में उज्ज्वला योजना किस तरह से क्रांतिकारी बदलाव लाई है, यही इस बार की आवरण कथा बनी है। इतना ही नहीं, जीवन सुरक्षा के लिए बीमा योजना ने भी आम लोगों को एक संबल दिया है, जिसकी कहानी इस अंक में है।

आजादी की लड़ाई हो या विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देना, इस देश की माटी में समाहित है। ऐसे में महाराणा प्रताप, गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा और गुमनाम नायकों की कहानी भी इस अंक का हिस्सा है। हमारे युवा-छात्र किस तरह जीवन की चुनौतियों से पार पाएं, इसके लिए 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संवाद आपको निश्चित तौर पर प्रेरित करेगा।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने का देश का संकल्प आप सभी के लिए आंदोलन बन चुका है और बीते एक वर्ष में इस मुहिम ने जो बदलाव किया है, वह देश के 137 करोड़ लोगों की जन भागीदारी के बिना संभव नहीं था।

हमेशा की तरह अपना सुझाव देते रहिए।

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल-response-nis@pib.gov.in

जयदीप भटनागर

(जयदीप भटनागर)

आपकी बात...

आपकी पत्रिका मुझे नियमित रूप से मिल रही है। इसकी सामग्री बहुत ही सुन्दर और ज्ञानवर्धक है। आप खिलौना अंक निकाल रहे हैं इसके लिए बहुत - बहुत बधाई। खिलौने बच्चों की जरूरत ही नहीं उनकी दुनिया भी होती हैं इसलिए खिलौने ऐसे हों जिनसे बच्चों को कोई नुकसान न हो। उन्हें किसी तरह का चोट न लगे और खिलौनों में केमिकल का कम से कम इस्तेमाल हो जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकें।

डॉ. सुखेदव राव rudorajasthan@gmail.com

पत्रिका नियमित तौर पर प्राप्त हो रहा है। अप्रैल प्रथम अंक पढ़कर काफी खुशी हुई। सभी लेख ज्ञानवर्धक है। मोबाइल पर पेज पलटकर पत्रिका पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगता है और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। आशा है आगे भी आप इसी तरह नियमित रूप से पत्रिका भेजते रहेंगे।

गणेश रवि
ganeshravi102@gmail.com

मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस पत्रिका में आम लोगों के बारे में जानकारी रहती है। लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल जैसे आधुनिक उपकरणों के युग मे 'न्यू इंडिया समाचार' का प्रकाशन रोमांच पैदा करता है। साथ ही यह पत्रिका समग्र ऊर्जावान गतिशील भारत का दर्पण दिखाई देता है।

andeshwarmahan@gmail.com

अब डिजिटल कैलेंडर

भारत सरकार ने पहली बार डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप लॉन्च किया है। जीओआई एप पर सभी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम, प्रकाशन के साथ आधिकारिक अवकाश और तिथियों की जानकारी भी मिल जाएगी।

इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर लिंक
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

आईओएस लिंक
https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

मुझे 'न्यू इंडिया समाचार' के ताजा अंकों का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक पीडीएफ भी साथ में संलग्न करें जिससे मैं इसे सेव करके रख सकूं और जरूरत पड़ने पर सभी मुख्य बिंदुओं को दोहरा सकूं। आप इसे एक सुझाव समझ कर स्वीकार करें।

हेमंत कुमार दुबे
hdubey02@gmail.com

पत्रिका का यह पहल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। साथ ही सभी लेखों को पढ़कर अच्छा लगा। आशा करता हूं भविष्य में भी हम सब को इसी तरह जागरूक करते रहेंगे।

ajitkumarsurya25@gmail.com

आपका यह अंक अपने आप में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी समेटे हुए है। यह अंक बहुत ही उपयोगी और सार्थक है।

निर्भय कुमार मिश्रा
nirbhay.tec@gmail.com

हम सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी पत्रिका है। यह हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगी। मैं इस पत्रिका को 5 स्टार देता हूं।

himomprakashy5@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार का अंक नियमित तौर पर मिल रहा है जिसके लिए संपादक मंडल को हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका के हालिया अंक में 'इच्छा शक्ति से इतिहास रचने वाली महिलाओं को सलाम' शीर्षक बेहद ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है। कई ऐसी महिलाएं जिनकी कार्य क्षमता से हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे, उन्हें पत्रिका ने स्थान देकर सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त अन्य लेख भी सीमित शब्दों में व्यापक विश्लेषण है।

रचना उनियाल appusona80@gmail.com

'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका मिला। आपका यह कदम बहुत ही सराहनीय है। आप हम नागरिकों को अपनी पत्रिका के माध्यम से सरकार की नवीन योजनाओं की सूचना दे रहे हैं। बड़े गौरव की बात है कि यह पत्रिका निशुल्क है। आपका यह कार्य बेहद प्रशंसनीय और सराहनीय है। मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

न्यू इंडिया समाचार पत्र का ताजा अंक प्राप्त हुआ। बहुआयामी योजनाओं, विविध समाचारों और देश विदेश की अनेकों ताजा खबरों, सूचनाओं और सार्वजनिक हितों से संबंधित तथ्यों से परिचित होने का सौभाग्य मिला।

kheemanandpenday1979@gmail.com

योग से हो निरोग, सीखें और सिखाएं, पुरस्कार पाएं

सत्य का पता चल जाने के बाद भ्रम कहां होगा? मन साफ होने पर रोग कहां होगा? श्वास नियंत्रित होने के बाद मृत्यु कहां होती है? इसलिए योग के प्रति समर्पित हों। योग की महत्ता पर ये विचार हैं आधुनिक योग के जनक माने जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के, जिनके शिष्यों में बीकेएस अयंगर जैसे योग गुरु भी शामिल रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज दुनिया योग और उसमें भारत के योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है, तब भारत उसके प्रसार के लिए हर कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का प्रसार करने और उसे बढ़ावा देने के प्रति समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए योग पुरस्कार की शुरुआत की थी। योग दिवस के मौके पर हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है। 21 जून 2021 को होने वाले योग दिवस के मौके पर दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग गुरु के. पट्टाभि के मुताबिक योग सच्चा आत्मज्ञान है, एक आंतरिक सफाई है। अगर आप योग के प्रति समर्पित किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें पीएम योग पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित कर सकते हैं।

स्टैंड अप इंडिया से आत्मनिर्भर हो रहे गांव और छोटे शहर

महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच अपना बिजनेस शुरू करने और उसमें अन्य लोगों को रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'स्टैंड अप इंडिया' योजना ने बीते पांच साल में बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। इसी साल 23 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक इसके तहत 1.14 लाख से अधिक खातों के लिए 25,586 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की जा चुकी है। यह योजना जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में पहल को आगे बढ़ाते हुए इसका विस्तार अब वर्ष 2025 तक किया गया है। इस योजना में जरूरतमंद उद्यमियों खासतौर से महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ हुआ है। इसका फोकस गांव और छोटे शहरों में रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की गतिविधि को बढ़ाना रहा है क्योंकि अधिकांश आबादी वहीं निवास करती है।

डिजिटल भुगतान: भारत ने चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ा

महामारी से जूझने में ही नहीं, भारत ने हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की राह दिखाई है। कोरोना काल में जब लोग घरों में बंद थे, देश ने डिजिटल भुगतान के मामले में एक वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 2020 में ट्रांजेक्शन की ग्लोबल टैली में अव्वल स्थान बनाया है। इस दौरान भारत में सबसे अधिक 25.5 बिलियन रियल टाइम ऑनलाइन लेनदेन हुआ। इसके बाद चीन में 15.7 बिलियन, दक्षिण कोरिया में 6 बिलियन, थाईलैंड में 5.2 बिलियन और ब्रिटेन में 2.8 बिलियन लेनदेन हुआ। शीर्ष 10 देशों में 1.2 बिलियन लेनदेन के साथ अमेरिका नौवें स्थान पर रहा।

समाचार-सार

4 करोड़ घरों में 'डीडी फ्री डिश' बना मुफ्त मनोरंजन का जरिया

मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए उपहार बन चुकी 'डीडी फ्री डिश' सेवा लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज, स्पोर्ट्स, शिक्षा समेत करीब 161 से ज्यादा मुफ्त चैनलों की सुविधा, सस्ते टीवी सेट, आर्थिक गति, पुराने जमाने के फिल्म-संगीत पर आधारित डीडी रेट्रो चैनल और फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर बड़े प्रसारकों के आने से मुफ्त मनोरंजन की सुविधा पहुंचाने वाली 'डीडी फ्री डिश' के ग्राहकों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है जो 2025 तक 5 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। यह प्रसार भारती की एक मल्टी-चैनल फ्री-टू-एयर डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा है। इसका उद्देश्य मुफ्त में लोगों को गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वैकल्पिक और किफायती मंच प्रदान करना है।

मसाला किसानों की अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच होगी आसान

भारतीय मसालों की सुगंध ने दुनिया को हमेशा से आकर्षित किया है। इस संपदा पर कब्जे के लिए कई संघर्ष भी हुए हैं, क्योंकि तब भारत के पास निर्यात करने का साधन नहीं हुआ करता था। जबकि भारत मसालों में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2019-20 में मसाला निर्यात 3 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया था। ऐसे में केंद्र सरकार मसाला किसानों की पहुंच को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए ब्लॉक चेन संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस बनाने जा रही है। इसके लिए भारतीय मसाला बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) इंडिया के एक्सलेरेटर लैब ने एक समझौता किया है। ब्लॉकचेन डिजिटल आधारित लेन-देन का रिकॉर्ड रखने वाला लीक प्रूफ सिस्टम है।

प्रगति का हाईवे, निर्माण की नई दिशा

भारत आज विश्व के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण कर रहा है। पिछले 7 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91, 287 किमी से बढ़कर 1,37, 625 किमी हो गई है जो 2014 के मुकाबले 50% अधिक है। सड़क मार्ग में 2.2% राजमार्ग का हिस्सा है, जबकि 40% ट्रैफिक इसी पर आवागमन करता है। इसलिए केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में इसका बजट साढ़े 5 गुना बढ़ाया है। वर्ष 2015 में 33, 414 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 1,83, 101 करोड़ रुपये हो गया है। अगर प्रगति की रफ्तार को तुलनात्मक तौर से देखें तो 2010-14 के बीच महज 5865 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और 4918 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। जबकि 2015-21 के दौरान 10,855 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और इसमें से 8989 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।

अमृत महोत्सव के समापन के साथ सबको आवास का सपना साकार

जब देश आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह मना रहा होगा, गांवों में सभी को पक्के मकान का सपना भी साकार हो रहा होगा। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री अवास योजना में ग्रामीणों के लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) तैयार की गई थी। इस सूची में शामिल 2.14 करोड़ पात्र परिवारों में से 1.92 करोड़ यानी 90 फीसदी घरों को मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से 1.36 करोड़ यानी 71 फीसदी आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं।

गोखले: जिन्हें खुद बापू ने महात्मा कहा

गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्हें विपरीत धाराओं में चलने वाली दो शख्सियतों महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक गुरू होने का सम्मान हासिल है। 19 फरवरी 1915 को जब गोखले का देहांत हुआ तो गांधी जी ने कहा था, "गोखले क्रिस्टल की तरह साफ थे। एक मेमने की तरह दयालु थे। एक शेर की तरह साहसी थे और इन राजनीतिक हालातों में एक आदर्श पुरुष थे।"

महाराष्ट्र के रत्नागिरि में 9 मई 1866 को ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पर माता-पिता शिक्षा का महत्व जानते थे सो उन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई। मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज से 1884 में परीक्षा पास करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भारत की उस पीढ़ी में शुमार है, जिन्होंने पहली बार विश्वविद्यालय की परीक्षा पास की थी। पढ़ाई पूरी कर गोखले प्रोफेसर बन गए। इसी दौरान उन्हें पहले महादेव गोविंद रानाडे और फिर दादा भाई नौरोजी का सानिध्य मिला। दोनों से कानून की बारीकियों को सीखते हुए कांग्रेस का सदस्य बनने के साथ फिरोजशाह मेहता से जुड़े। मेहता उस समय के मशहूर वकील थे और बहस के दौरान ब्रिटिश कानून की पोल खोलने के साथ सत्ता की आंख में आंख डालकर उसे अंधा कहने का साहस रखते थे। मेहता बंबई विधान परिषद के सदस्य थे। उन्हीं के साथ गोखले यहां तक पहुंचे। 1902 में ब्रिटिश वित्त सचिव एडवर्ड लॉ ने 7 करोड़ की बचत का बजट पेश किया। बजट बचत का था, सो हर तरफ उनकी तारीफ हुई। लेकिन ये वो वक्त था, जब देश के कई हिस्से अकाल से जूझ रहे थे। गोखले ने तार्किक आंकड़े देकर बताया कि कैसे अकाल के वक्त भी अंग्रेज सरकार ने लगान की दरें बढ़ाईं, सेना पर फिजूल खर्च किया और शिक्षा में खर्च पर कटौती की। परिषद में गोखले के भाषण ने सरकार की नकली छवि को उधेड़ कर रख दिया। गोखले मशहूर हो गए, कांग्रेस में भी उनका कद बढ़ा और 1905 में मात्र 39 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। कांग्रेस में उस समय दो धड़े थे। एक गरम दल, जिसकी अगुवाई बाल गंगाधर तिलक के हाथों में थी, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र ढंग से विरोध के हिमायती थी। दूसरा था, नरम दल। इसकी कमान थी, गोखले के हाथ में, जिनका मानना था कि भारतीयों को पहले शिक्षित होना चाहिए, तभी वह बतौर नागरिक अपना हक यानी आजादी हासिल कर पाएंगे। 1912 में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के न्यौते पर गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जब भारत लौटे गोखले ने उनसे कहा, "यदि देश को समझना है तो इसके करीब जाओ। पूरे देश को देखो, समझो। तब ही अपनी रणनीति बनाओ। बैरिस्टर गांधी महात्मा और बापू तक अपने सफर में गुरू के दिखाए इसी रास्ते पर चलते रहे।"

> *गोपाल कृष्ण गोखले अपार ज्ञान से परिपूर्ण एक महान व्यक्तित्व। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया।*
>
> — नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

देश में व्याप्त छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ गोखले जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। भारतीय शिक्षा को विस्तार देने के लिए उन्होंने 'सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी' की स्थापना भी की थी। 'मार्ले-मिंटो सुधार' का बहुत कुछ श्रेय गोखले के प्रत्यनों को दिया जाता है, जिनके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को जगह दी गई थी। कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले स्वदेशी का विचार भी गोखले की ही देन थी, जिस पर आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन खड़ा किया। महज 48 साल की उम्र में 19 फरवरी 1915 को गोखले का निधन हो गया। ●

राष्ट्रनीति... आत्मनिर्भर भारत की पटकथा

12 मई भारत के वर्तमान और भविष्य की ऐसी तारीख बन गई है जो एक जन आंदोलन के रूप में राष्ट्र की दशा-दिशा तय कर रही है। यह तारीख है कोरोना जैसी भयावह महामारी के बाद देश को 'वोकल फॉर लोकल' की दीर्घकालिक सोच के साथ आत्मनिर्भरता को जन आंदोलन की ओर ले जाने की। प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम है कि भारत निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा देश बन गया है और 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड' का मंत्र हो रहा है साकार

राष्ट्रनीति, राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सदियों में अक्सर ऐसी कोई घटना या सोच उभर कर देश के सामने आती है जब गरीब, अमीर, युवा, बुजुर्ग, महिला-पुरुष सब एकजुटता के साथ राष्ट्र निर्माण की उस सोच को साकार करने में जुट जाते हैं। इसी 'राष्ट्रनीति' ने पिछले साल 12 मई को देश को ऐसी दिशा दी जो भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हुई, बल्कि विदेशी वस्तुओं के प्रति आम लोगों को आकर्षित करने वाली धारणा धराशायी हुई और स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्साह ने उसे जन आंदोलन बना दिया। इसकी बानगी विशाखापत्तनम के वेंकट मुरली प्रसाद की चिट्ठी से मिलती है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चंद महीने पहले लिखी थी। वेंकट लिखते हैं, "मैं 2021 के लिए अपना एबीसी इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं।" पहले तो प्रधानमंत्री को भी यह समझ नहीं आया कि यह एबीसी क्या है। लेकिन जब उन्होंने पत्र के साथ संलग्न सूची देखी तब उन्हें मालूम पड़ा कि अंग्रेजी की इस एबीसी का मतलब है- आत्मनिर्भर भारत चार्ट । इस बेहद दिलचस्प सूची में वेंकट ने उन सभी चीजों का जिक्र किया था, जिसका प्रयोग वे अपनी दिनचर्या में करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोनिक्स, स्टेशनरी, अपनी जरूरत की वस्तुएं आदि लिखी हुई थी। वेंकट अपनी चिट्ठी में अपना संकल्प प्रधानमंत्री को बताते हैं कि अब वे उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे जिनमें देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। वह आगे लिखते हैं, "हम जाने-अनजाने में उन विदेशी वस्तुओं-उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी इस उत्साह में जोड़ते हैं, "हमें इस भावना को बनाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि आप भी एक सूची बनाएं और दिन-भर में हम जो चीजें काम में लेते हैं, उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि कौन सी, विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है या एक प्रकार से हमें बन्दी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और यह तय करें कि आगे से भारत में बने और भारत के लोगों के मेहनत-पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। एक संकल्प देश के लिए भी जरुर लें।"

आत्मनिर्भर भारत पैकेज...

कोरोना ने जनजीवन ही नहीं देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे फिर से गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई से 17 मई 2020 तक 5 चरणों में 20.97 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0 का पूरा खाका देश के सामने रखा। 12 अक्टूबर 2020 को 73 हजार करोड़ रु. के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 और 12 नवंबर 2020 को 2 लाख 65 हजार 80 करोड़ रु. के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की गई। आइए समझते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किस चरण में क्या मिला और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ा....

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0

- **वन नेशन वन राशन कार्ड:** पूरे देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी राशन खरीदने की सुविधा।
- **पीएम स्वनिधि योजना:** 23.97 लाख लोन स्ट्रीट वेंडर को 10 हजार रु. तक के लोन वितरित।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 157.44 लाख किसानों को मदद।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:** 9 दिसंबर 2020 तक 2,182 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
- **इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए:** 25000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में वितरित किए जा चुके हैं।
- **इसीएलजीएस 1.0:** अब तक 2.05 लाख करोड़ रुपये 61 लाख लोगों को स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- **पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड रु. स्वीकृत किए गए हैं।
- **एनबीएफसी/एचएफसी के लिए लिक्विडिटी स्कीम:** इस योजना के अंतर्गत अब तक 7227 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
- **लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स:** अब तक 1,18,273 करोड रुपये के लोन मंजूर किए गए।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0

फेस्टिवल एडवांस: फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत एसबीआई उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम: एलटीसी कैश वाउचर योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में लांच की गई थी। इस योजना की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है।

सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को 25000 करोड रुपये अतिरिक्त पूंजी व्यय के तौर पर दिए गए हैं। 11 राज्यों को पूंजी व्यय के लिए 3621 करोड़ का लोन।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0

- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार देने पर बल दिया।
- इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में कोविड काल में संकटग्रस्त हेल्थकेयर और 26 अन्य सेक्टरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।
- उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत। अभी 10 नए सेक्टर जोड़े गए हैं। कुल 13 सेक्टर में पीएलआई दी जानी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) में 18000 करोड रुपए का अतिरिक्त योगदान दिया गया, ताकि मांग बढ़ने के साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो।
- 31 दिसंबर 2021 तक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए बैंक गांरटी के तौर पर 10 की जगह 3% सिक्योरिटी तय की गई।
- घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स छूट का फायदा।
- किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी के लिए 65 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अतिरिक्त 10 हजार करोड़ रुपये दिए गए।
- कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई।
- कोविड वैक्सीन के शोध और विकास के लिए 900 करोड़ रुपये।

दरअसल प्रधानमंत्री ने कोरोना के कुप्रभाव से न सिर्फ देश को बचाने का बीड़ा उठाया, बल्कि बेपटरी होने वाली अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रगति की रफ्तार भरने का खाका भी तैयार कर लिया था। ताकि दोनों मोर्चों पर जन और देश का नुकसान कम से कम हो। तीसरे लॉकडाउन के बाद 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ कोरोना के पूर्व और बाद की दुनिया की बात

सुधारों का असर | फिर पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था...

- **जीडीपी का 15 फीसदी पैकेज:** केंद्र सरकार द्वारा घोषित 29.87 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 15 फीसदी था। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए और भी कई देशों ने आर्थिक पैकेज जारी किए। जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1%, अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 13%, स्वीडन ने 12%, जर्मनी ने 10.7%, स्पेन ने 7.3% और चीन ने अपनी कुल जीडीपी का 3.8% के बराबर आर्थिक पैकेज इस दौरान जारी किया।

- **जीडीपी विकास दर फिर पॉजिटिव:** मुश्किल वक्त में यह केंद्र सरकार की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि सख्त लॉकडाउन के बाद जब जीडीपी विकास दर -23.9% तक नीचे चली गई थी और दुनियाभर के आर्थिक विशेषज्ञों ने हमारे यहां मंदी की आशंका जताई थी, वो जीडीपी विकास दर तीसरी तिमाही में ही 0.4% के आंकड़े के साथ 'वी आकार' में रिकवरी करते हुए सकारात्मक आंकड़े पर लौट आई।

- **रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश:** अप्रैल 2020 में जिस वक्त देश में सख्त लॉक डाउन लगा हुआ था, तब से जनवरी 2021 तक केवल 10 महीने में देश में 72.12 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह हुआ है। यह अभी तक के इतिहास में किसी भी वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

समाज के हर वर्ग का ख्याल

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज	1,92,800 करोड़ रुपये
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्न योजना	82,911 करोड़ रुपये
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0	73,000 करोड़ रुपये
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0	2,65,080 करोड़ रुपये
रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय	12,71,200 करोड़ रुपये
कुल	29,87,641 करोड़ रुपये

- **आयात कम हुआ, निर्यात बढ़ाया:** लॉकडाउन के ठीक पहले तक मार्च 2020 में भारत का कुल विदेशी निर्यात जहां केवल 21.49 अरब डॉलर था, मार्च 2021 में यह 58.23% की बढ़ोतरी के साथ 34 अरब डॉलर हो गया है। यहीं नहीं, इस दौरान भारत शीर्ष 5 वस्तुओं के आयात में 13 से 90 फीसदी तक की कमी आई है।

- **रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह:** मार्च 2021 में 1.23 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है। अक्टूबर 2020 से यह लगातार छठा मौका है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये के पार रहा है।

की बल्कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था, मांग पर जोर देकर आत्मनिर्भर भारत के भविष्य की लकीर खींच दी। जिसके लिए उन्होंने लोकल उत्पादों को तरजीह देते हुए वैश्विक पहचान दिलाने का आह्वान किया। इसी का नतीजा है कि आज भारत में विदेशी निवेशकों का उत्साह बढ़ा है तो आयात में कमी करते हुए निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। पर्व, त्योहार, शादी-विवाह, हर मौके पर आज लोग 'लोकल' के लिए 'वोकल' होते दिख रहे हैं।

पहले जन-जीवन, फिर राष्ट्र को रफ्तार

देश में पहला लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लगा और केंद्र सरकार ने अगले दिन ही 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रु. की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एलान कर गांव-गरीब-किसान की फिक्र की। इतना ही नहीं, 12 मई को उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान किया तो उसकी भी मुकम्मल तैयारी लॉकडाउन के दौरान ही कर ली थी। इस एलान से पहले उन्होंने उद्योग जगत को भरोसे मे लेना हो या फिर दवा कंपनी, चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, आईटी, और तमाम सेक्टरों से जुड़े लोगों के साथ वर्चुअल बैठकें की तो दलगत भावना पर देशहित को तरजीह देते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस दौरान पांच बार भरोसे में लिया। जिस तरह से मोदी ने इस अभियान को अंजाम दिया है, उससे आने वाले समय में भारत निर्यातक देशों में तेजी से आगे आएगा।

प्रधानमंत्री के एलान के बाद जिन पांच चरणों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज का एलान किया, वह भी रणनीतिक था। पहले दिन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली एमएसएमई में सुधार के साथ मजबूती के जरिए उत्पादन और आपूर्ति पर जोर दिया तो दूसरे दिन किसान, मजदूर, रेहड़ी-पटरी, रोजगार सृजन, आवास जैसी पहल का एलान हुआ। तीसरे दिन कृषि उत्पादन और पशुधन की परवाह की गई तो चौथे दिन देश के आधारभूत ढांचे को गति देने की पहल हुई, जबकि आखिरी दिन ग्रामीण, स्वास्थ्य के ढांचे में कोरोना के बाद की बदली परिस्थिति के लिहाज से कैसे बदलाव हो इसकी चिंता की गई। ●

टीका उत्सव

कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई

अब 18 वर्ष से ऊपर सभी को टीका

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से कई राज्यों में घातक परिणाम सामने आए हैं। नए रोगी, सक्रिय मरीज, संक्रमण दर सबने रिकॉर्ड तोड़े तो अब कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट के मंत्र के साथ अब टीका उत्सव के जरिए देश ने कसी कमर

पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले फिर एक बार तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में भी इसकी दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में संक्रमण के घातक आंकड़े सामने आए हैं। इस साल फरवरी में जो महामारी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी, वो फिर एक बार भयावह रूप में पूरी दुनिया के सामने है। हालत यह है कि सीबीएसई के तहत आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है तो 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उधर, केंद्र सरकार ने जहां देश में टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज किया है, वहीं लोगों को उचित इलाज मिल सके इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत में 16 जनवरी को हेल्थकेयर वर्कर्स को टीका लगाने के साथ कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगने लगी थी। 1 मार्च से 60 वर्ष से ऊपर के और 45-59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वैक्सीन लगने लगी थी। इस बीच, कोरोना की दूसरी लहर हावी हुई और सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन में शामिल कर लिया। अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोगों के लिए टीकाकरण की शुरूआत की गई है।

दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक, रिकॉर्ड केस आए सामने

19 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में 2.74 लाख कोरोना केस सामने आए हैं। यह एक दिन में मिले संक्रमित मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। भारत में मिल रहे नए संक्रमित मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा हिस्सा 10 राज्यों, महाराष्ट्र, मध्य

सबसे तेज: 85 दिनों में 10 करोड़ टीके का रिकॉर्ड

भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में 10 अप्रैल को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत केवल 85 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी हैं। टीकाकरण की यह रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुल टीकाकरण के मामले में भारत से आगे चल रहे अमेरिका में 85 दिन में 9.2 करोड़, जबकि चीन में 85 दिन में 6.14 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई थीं। इन दोनों देशों में टीकाकरण कार्यक्रम भारत से पहले शुरू हो गया था। 18 अप्रैल तक देश में कुल 12 करोड़ 38 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

टीके के साथ सावधानी भी जरूरी

19,29,329
कुल सक्रिय मरीज

1,29,53,821
ठीक हुए मरीज

1,78,769
मृत्यु

86.00%
रिकवरी रेट

मृत्यु दर (1.19%) आंकड़े 18 अप्रैल तक

स्पूतनिक- V को मंजूरी, बाकी को भी जल्द

कोवीशील्ड और कोवैक्सिन के बाद अब रूस की स्पूतनिक-v वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। स्तूपनिक-v वैक्सीन को भारत में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरी तैयार करेगी। व्यापक परीक्षण के बाद इस वैक्सीन की प्रभावशीलता करीब 91.6 प्रतिशत सामने आई। तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिलने से टीकाकरण कार्यक्रम में और तेजी आएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करने के लिए अन्य देशों में मंजूरी हासिल कर चुकीं वैक्सीन को भी भारत में भी उपयोग की मंजूरी जल्द दे सकती हैं। हालांकि पहले 100 लोगों पर इनका ट्रायल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कुछ और बिंदुओं पर दिया जोर

- कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीन की बर्बादी को रोकना है। सभी को मिलकर इस पर ध्यान देना चाहिए।
- वैक्सीन के बाद भी मास्क और कोविड के अन्य प्रोटोकॉल जैसे- दो गज की दूरी, का हमें लगातार ध्यान रखना चाहिए।
- ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके के लिए प्रेरित करें। इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर 11 अप्रैल से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक देश में टीका उत्सव की शुरुआत की गई है।
- हमें चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला- Each One- Vaccinate One, यानी जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें।
- Each One- Treat One, यानि जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें।
- Each One- Save One, यानि मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी Save करूं और दूसरों को भी Save करूं, इस पर बल देना है।
- चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में, 'माइक्रो कन्टेनमेंट जोन' बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग 'माइक्रो कन्टेनमेंट जोन' बनाएं।

प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के मरीजों की है।

रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करेंगे...

केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों को भी निर्धारित किया गया है। भारत में अभी 7 कंपनियां इस इंजेक्शन का उत्पादन करती हैं। इनके पास एक माह में 38 लाख 80 हजार डोज तैयार करने की क्षमता है। केंद्र सरकार ने इंजेक्शन के साथ ही इसके एपीआई (कच्चे माल) के निर्यात पर भी रोक लगाई है। साथ ही, सभी घरेलू निर्माताओं को अपनी वेबसाइट पर स्टॉकिस्ट और वितरकों का पूर्ण विवरण देना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर पूरे डाटा पर नजर रखेंगे, ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग न की जा सके। राज्यों में जरूरत के हिसाब से निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चला रहा है। देशभर में 162 ऑक्सीजन संयत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 33 संयत्र स्थापित हो चुके हैं। मई तक बाकी संयत्र भी स्थापित हो जाएंगे। ●

भीमा ने दी अंग्रेजों को चुनौती, झलकारी पर था झांसी को नाज

10 मई 1857... वो तारीख जब भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था...अंग्रेजों ने भले ही इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया, लेकिन यह आज भी प्रतीक है हमारे स्वाभिमान और सम्मान की खातिर की गई उस क्रांति का जिसका असर आने वाले समय में प्रत्येक भारतीय पर पड़ने वाला था और जिसके चलते 164 वर्ष बाद भी आज हम इसे याद कर रहे हैं...

भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही दिवंगत सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं, जहां करोड़ों-करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब ये अहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक और कितना गौरवशाली है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जाग्रत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परम्पराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है। इस तरह देखें तो इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा, स्वाधीनता संग्राम की परछाई और आजाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी शामिल है। इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों, अलग-अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है।

> “कोई भी संकल्प बिना समारोह के सफल नहीं है। जब कोई संकल्प समारोह का रूप ले लेता है तो लाखों लोगों की प्रतिज्ञा और ऊर्जा उसमें जुड़ जाती है। 75 वर्षों का समारोह 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी के साथ किया जाना है तथा लोगों की यह भागीदारी इस समारोह के मूल में है। इस समारोह में 130 करोड़ देशवासियों की अनुभूतियां, सुझाव तथा सपने शामिल हैं।”
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

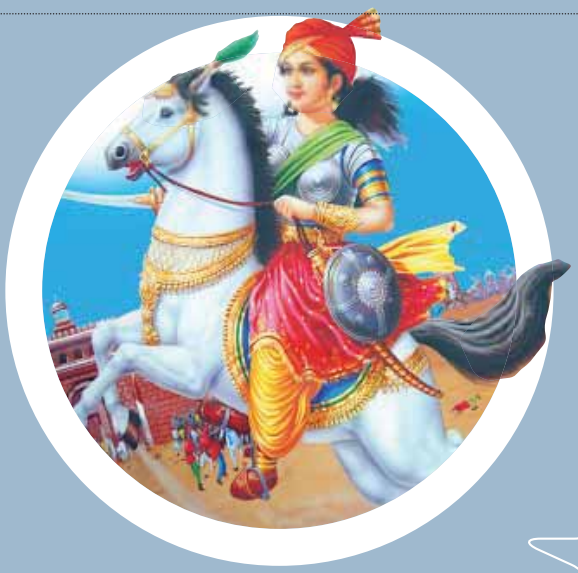

लक्ष्मीबाई बन कर रण में ललकार उठी थी झांसी की झलकारीबाई

देश और दुनिया में अपनी वीरता का परचम लहराने वाली झांसी वाली रानी यानी लक्ष्मीबाई को भला कौन नहीं जानता... लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता के दम पर अंग्रेजों की नाक में दम कर उनकी सत्ता की नींव हिला कर रख दी थी। वीरता के मामले में लक्ष्मीबाई को साक्षात दुर्गा का अवतार माना जाता है, तो उनकी सहयोगी झलकारी बाई को वीरता में उनका अक्स। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला दुर्गा दल की सेनापति थीं। ऐसा कहा जाता है कि एक गरीब और दलित परिवार में जन्मीं झलकारी बाई का चेहरा बहुत हद तक लक्ष्मीबाई से मिलता-जुलता था। यही वजह है कि अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्होंने कई बार रानी का भेष धरा और युद्ध के मैदान में उतरीं। रानी को झांसी के किले से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई के वेश में मैदान में उतरी थीं। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि झलकारी सीधे अंग्रेज जनरल ह्यू रोज के सामने पहुंची। झलकारी को रानी समझ रहे अंग्रेज खुश हो गए। उन्होंने पूछा-तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? रानी के वेश में झलकारी ने कहा- मुझे फांसी दो। कहा जाता है कि यह उत्तर सुनकर अंग्रेज जनरल के मुंह से निकल पड़ा- "यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा।" अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड के लोगों के जेहन में जिंदा है और लोग बड़ी शिद्दत के साथ उन्हें याद करते हैं।

अंग्रेजों की गोलियों का जवाब जिसने अपने तीरों से दिया निमाड़ का रॉबिनहुड

मध्य प्रदेश का खरगौन आदिवासी भीमा नायक की कर्मभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इस हिस्से को निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इस क्षेत्र में भीमा नायक ने अपने 10 हजार आदिवासी साथियों के साथ किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला कर रख दी थीं।

उनका कार्यक्षेत्र बड़वानी रियासत से लेकर महाराष्ट्र के खानदेश तक रहा है। अंग्रेजी बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से करने वाले भीमा अंग्रेजों के खजाने को लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। इसलिए उन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। भीमा को मनाने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रलोभन भी दिए। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सेना जब भीमा को ऐसे नहीं पकड़ पाई तो उन्हें उनके ही किसी करीबी की मुखबिरी पर धोखे से पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद भीमा नायक को काला पानी की सजा हुई। उन्हें अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में रखा गया। यातना दी गई। 29 दिसम्बर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में वे शहीद हुए।

जीवन को गढ़ने का अवसर है | परीक्षा

किसी को भी आश्चर्य होता है कि एक समय में कई महत्वपूर्ण निर्णयों से निपटने वाले दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक को, बच्चों के साथ अपने जीवन के एकत्र ज्ञान का हिस्सा साझा करने का समय मिल जाता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ही नहीं, उनके माता-पिता और शिक्षकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अच्छे अर्थों में, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक के नाते, हर साल की तरह इस साल भी 'परीक्षा पर चर्चा' के चौथे संस्करण में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले मंत्र दिए, ताकि छात्र बिना किसी तनाव के मुस्कराहट के साथ परीक्षा दें

क्या सिर्फ अच्छे अंक लाने का मतलब यह है कि हम सफल हैं? यह एक सवाल है जो हर वर्ष परीक्षा के वक्त पर हर छात्र के मन में कौंधता है। दरअसल, यह इसलिए क्योंकि किसी भी परीक्षार्थी की सफलता और मेहनत का मूल्य लोग परीक्षा में आए उसके अंक देखकर ही देते रहे हैं। लेकिन अब धारणा टूटनी चाहिए। परीक्षा तनाव लेने का नहीं तमाम कसौटियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने का वक्त है। लगातार चौथे साल 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "छात्र इन परीक्षाओं को ही अपनी मंजिल न समझें यह तो मात्र एक जीवन के पड़ाव में आने वाली कसौटी की तरह है और इस तरह की तमाम कसौटियों से लड़ने के लिए हमें खुद को तैयार रखना चाहिए।"

कोरोना संकट के चलते पहली बार यह कार्यक्रम वर्चुअली हुआ। इस दौरान दुनिया भर के लाखों बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने एक दोस्त के नाते छात्रों-अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण बात कही, "आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे एक ही हैं। अच्छी किताबें, फिल्में, कहानियां, कविताएं, मुहावरे, अच्छे अनुभव ये सब प्रशिक्षण के ही उपकरण हैं। ये परीक्षा पर चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है।"

> *जब किसी विषय को आप आत्मसात कर लेते हैं तो वह विचार प्रवाह का हिस्सा बन जाता है जो स्मृति पटल से कभी विलुप्त नहीं होता।*
>
> नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

परीक्षा रुकी, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है 'परीक्षा पर चर्चा'

देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक संजीदा अभिभावक का किरदार अदा किया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों की सेहत से जुड़ी चिंताओं की खास चर्चा की गई। जिसमें यह सुझाव दिया गया कि परीक्षाओं को सिर्फ टाल दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा कि बच्चों के लिए किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं रोकी गई है, लेकिन उससे सप्ताह भर पहले परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री का मकसद परीक्षा के तनाव से ही मुक्त करना नहीं, बल्कि छात्रों को अपने भविष्य के लिए एक ऐसी जीवनशैली से परिचित कराना है, जिससे नवांकुर, नव पुष्पित और पल्लवित हो सकें।

दोस्त बनकर प्रधानमंत्री ने परीक्षा से तनाव और भय से मुक्त होने को दिए मंत्र

छात्र ऐसे हों परीक्षा के तनाव से मुक्त

- **परीक्षा से डरें नहीं:** यह पहली बार या अचानक नहीं आया है। हर साल मार्च-अप्रैल महीने में परीक्षा होती है। आपको डर एग्जाम का नहीं है। आपको डर किसी और का है, और वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है, कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है।
- **तनाव परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ें:** अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी, आपने कर ली है। अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए।
- **सभी विषय पर समान समय दें:** आपको अपनी ऊर्जा सामान रूप से लगानी चाहिए। सभी विषयों में बराबर-बराबर, आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं, तो उन घंटों में हर विषय को समान भाव से पढ़िए। सभी पर सामान रूप से अपना समय दीजिए।
- **संकल्प की राह:** सपनों के लिए सोते रहना सही नहीं है। अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे? जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देगा।
- **दबाव मुक्त रहें:** आप जो पढ़ते हैं, वो आपके जीवन की सफलता-असफलता का पैमाना नहीं है। जीवन में जो करेंगे उससे यह तय होगा, इसलिए समाज, माता-पिता और अन्य लोगों के दबाव से बाहर निकलें।
- **क्रांतिवीरों से लें प्रेरणा:** आजादी की लड़ाई से जुड़ी अपने राज्य की 75 घटनाएं खोजकर निकालिए। ये किसी व्यक्ति-क्रांतिवीर से जुड़ी हो सकती हैं। इनको अपनी मातृभाषा में लिखिए।
- **साल भर की योजना बनाएं:** पूरे साल का प्रोजेक्ट बनाइए और डिजिटल तरीके से इसे कैसे करें, इसके लिए शिक्षकों, माता-पिता, दादा-दादी से बात करिए।
- **खाली समय एक खजाना है:** खाली समय को खाली मत समझें। यह एक अवसर है, दिनचर्या में खाली समय नहीं होगा तो जीवन रोबोट हो जाएगा। जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें।

आत्मनिर्भरता को बनाएं जीवन मंत्र: आज मैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना चाहता हूं। यह बड़ा एग्जाम है जिसमें हमें शत-प्रतिशत मार्क्स लेकर पास होना ही है। ये हैं- भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वोकल फॉर लोकल को जीवन मंत्र बनाना।

शिक्षक सिखाएं प्रबंधन और व्यावहारिक ज्ञान

समय प्रबंधन के गुर सिखाएं: विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, उसके तौर-तरीके बताएं। पाठ्यक्रम से बाहर जाकर भी उनसे बात करें और मार्गदर्शन दें।

उपदेशात्मक नहीं, व्यवहारिकता बताएं: बच्चे बहुत चंचल होते हैं। वह बड़ों द्वारा कही गई बातों से ज़्यादा बड़ों की कार्यशैली और उनके व्यवहार का अनुसरण करते हैं। इसलिए हम उपदेशात्मक न होकर अपने व्यवहार से बच्चों में अच्छे आचरण का बीज बोएं।

अभिभावक बनें आदर्श

बच्चों पर दबाव न बनाएं: यह जिंदगी बहुत लंबी है, जिसमें परीक्षा एक छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर बाहर का दबाव खत्म हो गया, तो परीक्षा का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। आत्मविश्वास फलेगा-फूलेगा सो बच्चों को घर में सहज तनावमुक्त जीवन दें।

आप ही हैं बच्चों के आदर्श: बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जो आप कहेंगे, उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो आप कर रहे हैं, वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित होता है।

बच्चों की पसंद-नापसंद को जानें: अपने बच्चों के साथ जुड़ें, उनकी पसंद-नापसंद को जानें, यह पीढ़ी के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा।

आपका बच्चा खुद होगा प्रकाशित: एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर-प्रकाशित नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं, वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए जो आपके प्रयासों से संभव है।

बच्चों को भय से मुक्त रखें: बच्चों में कभी भी यह भय पैदा न करें कि ये होगा तो ऐसा होगा। ऐसी कोशिश मत कीजिए। यह तरीका लगता आसान है लेकिन इससे नकारात्मक मोटिवेशन की संभावनाए बढ़ जाती हैं।

पारंपरिक खान-पान की बात करें: हमारी खाने की जो पारंपरिक चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। उसकी जो विशेषता है, उसकी बात करें।

बच्चों के साथ बढ़ाएं नजदीकी: अगर आपको नवजीवन की ओर आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटा युवा बने रहना है तो अपने बच्चों के साथ दूरी कम कर नजदीकी बढ़ाइए। यह आपके लिए फायदेमंद है।

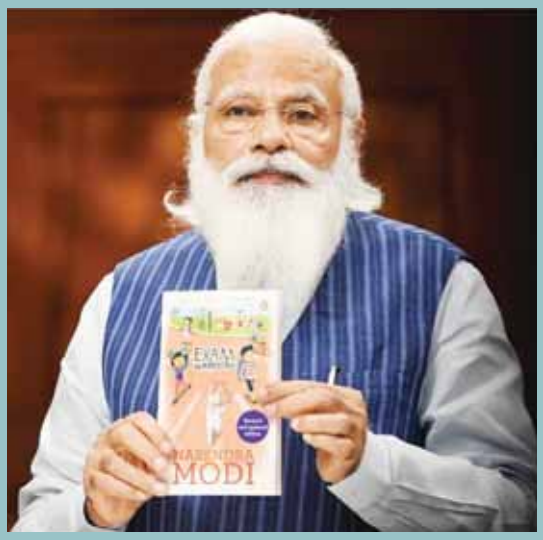

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देश-विदेश के कई छात्रों-अभिभावकों के सवालों के दिए जवाब

Q&A

आंध्र प्रदेश की छात्रा पल्लवी और कुआलालंपुर के छात्र अर्पण पांडे ने प्रधानमंत्री से पूछा कि परीक्षा के समय परीक्षा के भय को किस तरह से कम करें।

यह सिर्फ परीक्षा का डर नहीं है बल्कि यह आपके आसपास बने वातावरण का भय है, इसी कारण आपको लगता है कि यही सब कुछ है, यही जिंदगी है। इसी वातावरण के कारण ही आप आवश्यकता से अधिक सजग हो जाते हैं। जीवन बहुत लंबा होता है और यह परीक्षाएं जीवन के चरण मात्र हैं। माता-पिता, शिक्षकों और आमजन को छात्रों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। परीक्षा को किसी को जांचने मात्र के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए ना कि इसे जीवन और मृत्यु का विषय बना दिया जाना चाहिए। जो माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनके अध्ययन के प्रयास में लगे रहते हैं उन्हें अपने बच्चों की कमियों और अच्छाइयों दोनों का पता होना चाहिए।

आज माता-पिता के लिए बच्चे बड़े करना, थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है आज का ज़माना और आज के बच्चे। ऐसे में हम कैसे यह सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो?

प्रवीण कुमार, एक जाग्रत पिता के रूप में शायद मुझे ये पूछ रहे हैं, बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए, मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें। ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है या चाहते हैं, वैसी ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिएं। थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है, तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है। मुझे याद है एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से बात कर रहा था तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्ट अप शुरु किया है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्टार्ट अप शुरु किया और मेरी मां को जब पता चला तो मेरी मां ने तुरंत कहा 'सर्वनाश! यानि मां को इतना झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्ट-अप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव में, अपने बच्चे को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? और इसलिए, आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोर दें, हमें पहचान करना चाहिए। ●

मैन्युफैक्चरिंग हब से 1 करोड़ रोजगार की दिशा में बढ़ते कदम

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत देश को मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई 13 पीएलआई योजना से 5 वर्षों में 500 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मिलेगा। भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कैबिनेट ने अब तक 9 सेक्टर में पीएलआई को दी मंजूरी

करीब 2 लाख करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से अगले पांच साल में 520 बिलियन डॉलर की लागत का उत्पादन करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (उत्पादन के लिए प्रोत्साहन से जुड़ी योजना) देश की दिशा बदलेगी। 13 अहम सेक्टर में पीएलआई भारत की अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र को बहुत बड़ी उछाल की तरफ लेकर जाने का साधन बनने वाला है, जिससे नए प्रोजेक्ट लगेंगे, इंडस्ट्री का सर्किल बनेगा। इससे देश में ऐसा इको-सिस्टम बनेगा जिससे 1 करोड़ रोजगार के अवसर बनेंगे ताकि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 25 फीसदी तक पहुंचाया जा सके। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब तक 9 सेक्टर में पीएलआई को मंजूरी दे दी है जो उद्योग जगत और निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। बाकी के चार सेक्टर में भी इस योजना को लागू करने और कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

पीएलआई योजना की पृष्ठभूमि और लाभ

- लगभग 7 वर्षों से भारत की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरर्स उसको कैसे गति दे और युवाओं को अधिक अवसर मिले, इस दिशा में काफी बल दिया गया है।
- इस तरह से ठोस कदम पहले कभी नहीं उठाए गए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत पहली बार भारत की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कदम उठाया ताकि देश अपने बूते खड़ा हो सके।
- भारत अब विश्व में सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनेगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल चैंपियन बनने के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकेगा।

निश्चित तौर से 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के मंत्र के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की पीएलआई योजना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, निवेश को आकर्षक करने और देश को ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण अंग बनाने में सहायक होगी। ●

पीएलआई: अब तक इन सेक्टरों को मिली गति

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान | करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री
15000 करोड़ का प्रावधान, | करीब 1 लाख रोजगार के अवसर की संभावना।

आईटी हार्डवेयर प्रोडक्टस
7350 करोड़ रुपये का प्रावधान | देश में करीब 1.8 लाख रोजगार के अवसर।

सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए
4500 करोड़ रुपये का प्रावधान | 1.5 लाख अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में
12195 करोड़ रुपये का प्रावधान | करीब 40 हजार रोजगार के अवसर होंगे।

एसी-एलईडी बल्ब यानी श्वेत वस्तुएं
6238 करोड़ रुपये का प्रावधान | 4 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना।

पीएलआई जो पिछले वर्ष घोषित हुई

- **6940** करोड़ रुपये फार्मास्युटिकल्स एपीआई
- **40,951** करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
- **3420** करोड़ रुपये मेडिकल उपकरण

रोशन हुई रसोई उज्ज्वल हुई उम्मीद

हर घर रसोई गैस की सुविधा सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना भर नहीं है, बल्कि छह दशकों से संपन्न वर्ग और शहरों तक सीमित एलपीजी की सभी तक सुलभता ने आम लोगों के जीवन स्तर के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में किया अभूतपूर्व बदलाव। ऐसा उदाहरण पहली बार हमारे सामने है जब कि देश के संपन्न वर्ग के सहयोग से ही गांव-गरीब तक कोई योजना इस तरह से पहुंच पाई हो और 6 दशक तक जिस देश में एलपीजी की सुविधा मात्र 55 फीसदी घरों तक सीमित थी, उज्ज्वला के 8 करोड़ नए कनेक्शन के साथ अब 99.6 फीसदी घरों में एलपीजी पर खाना बन रहा है। भारत की इतनी बड़ी सफलता से अब घाना और बांग्लादेश जैसे देश भी हुए प्रेरित...

बचपन की एक कथा मुझे याद आती है। आप सब ने इसे स्कूल में पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत विद्वान लेखक थे। बहुत मशहूर कहानी- ईदगाह, उन्होंने 1933 में लिखी थी। इस कहानी का मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वह मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद कर ले आता है, ताकि खाना बनाते समय दादी के हाथ जल न जाए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता।
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री (उज्ज्वला लाभार्थियों से संवाद के दौरान)

पहले जब गैस नहीं थी तो दिन का आधा समय चूल्हा जलाने और खाना बनाने में बीत जाता था। बारिश के मौसम में मिट्टी के चूल्हे में पानी भर जाता था। काठ (लकड़ी) भी भीग जाता था, वो जलता भी नहीं था। बच्चे बारिश के मौसम में खाना भी नहीं खा पाते थे, भूखे रहते थे। मैं अपने बच्चों और परिवार को समय नहीं दे पाती थी। लेकिन, जब गैस दीदी ने आकर गैस कनेक्शन दिलवाया तब से बारिश के मौसम में परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अब परिवार के साथ बच्चे को भी समय दे पाती हूं।" ओडिशा के मयूरभंज की सुष्मिता के चेहरे पर सुकून की कहानी इकलौती नहीं है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की अर्जुमन आरा कहती हैं, "अब हमारा टाइम बचता है, पहले चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, खतरा रहता था। धुएं से काले बर्तन साफ करने में हमारा बहुत टाइम जाता था। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो अस्पताल ले जाने में सारा दिन चला जाता था। इससे हम एक टाइम का खाना नहीं पका पाते थे। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है तो इससे हमें बहुत सहुलियतें मिल गई है। रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा। अब हम सुबह ही उठकर 15 मिनट, आधा घंटे में ही खाना बना लेते हैं, खा भी सकते हैं और बच्चों को खिला भी सकते हैं। पहले लकड़ियां लाकर रखनी पड़ती थी और कभी-कभी तीन बजे से ही खाना बनाना पड़ता था। बच्चों को लकड़ी का धुआं लगता था, खांसते थे और खांसी से नींद से पहले ही उठ जाते थे। लेकिन अब धुएं से बच गए, समय बचा तो मैंने सिलाई का काम भी सीखा और अब उससे भी आमदनी होती है जिससे सिलेंडर आसानी से खरीद लेते हैं।"

छत्तीसगढ़ के रायपुर की मीना निर्मलाकर के घर का खर्च कम हुआ है और आस-पड़ोस का माहौल भी बदल गया है। तमिलनाडु की रुतरमा के लिए गैस चूल्हे पर इडली-डोसा बनाना आसान हो गया है। बिहार की गीता देवी, जूली, रज्जो देवी को भी लकड़ी जुटाने की मुश्किलों और धुएं से आंखों में जलन, सिर में दर्द और बच्चों को स्कूल भेजने में होने वाली देरी से मुक्ति मिल गई है। जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली ऐसी ही सफलता की कहानियां देश के हर कोने-कोने में मौजूद है, जिससे

समय से पहले पूरा सफर...

8 करोड़वां कनेक्शन

खाना पकाना पहले मेरे लिए बहुत मेहनत का काम था। लेकिन अब सिलेंडर और स्टोव मिलने के बाद मेरी मेहनत बचेगी।

आएशा शेख, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
(7 सितंबर 2019)

5 करोड़वां कनेक्शन

आंखों में अब धुआं नहीं लगेगा। सिलेंडर के लिए धन्यवाद मोदी जी...
तकदीरन, दिल्ली
(3 अगस्त 2018)

पहला कनेक्शन

आंखों में चूल्हे का धुआं लगता था, लकड़ी लाने की दिक्कत अलग। उज्ज्वला ने मेरी और परिवार की जिंदगी बदल दी।
गुड्डी देवी, बलिया, उत्तर प्रदेश
(1 मई 2016)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

स्वच्छ ईंधन.. बेहतर जीवन

शुरुआत

01.05.2016 को बलिया से लांच हुई।

1,37,483

करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में डीबीटीएल के जरिए हस्तांतरित की गई।

12800

करोड़ रुपये (1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) इस योजना पर कुल सामाजिक निवेश हुआ।

- **गिव इट अप अभियान से जुड़कर 1.08 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी**
- **रिफिलिंग को लेकर भी उत्साह है, 80 फीसदी से ज्यादा लाभार्थी ने पहली बार इस्तेमाल के बाद दूसरी बार भी रिफिल लिया।**
- **पहली बार रसोई गैस का प्रयोग करने वाले लाभार्थी औसतन साल में तीन बार सिलेंडर ले रहे हैं, जो बदलती हुई सोच का परिचायक है।**

08

करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य तय अवधि से पहले 7 सितंबर 2019 को हुआ पूरा।

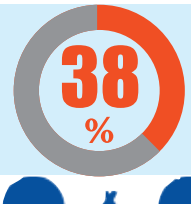

38% लाभार्थी परिवार यानी लगभग 3.05 करोड़ अनुसूचित जाति/जनजाति से

आम लोगों का जीवन आसान हो गया है और उसकी मूल वजह बनी है- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।

अंत्योदय की नीति और चुनौतीपूर्ण यात्रा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रसोई में पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले आदि पर खाना बनाने की वजह से निकलने वाले धुएं से ही हर साल करीब 5 लाख मौतें होती थी। इसमें अधिकांश महिलाएं होती थीं, जिनकी खराब सेहत का असर स्वाभाविक तौर पर पूरे परिवार पर पड़ता था। वायु प्रदूषण होता था, सो अलग। इसके बावजूद आजादी के इतने लंबे अरसे तक रसोई गैस जैसे स्वच्छ ईंधन को एक विशेष वर्ग तक ही सीमित रखा गया। जबकि पूर्व की सरकारें चाहती तो इसे देश भर में बढ़ा सकती थी। लेकिन 1955 से 2014 तक देश में जहां सिर्फ 13 करोड़ कनेक्शन थे, बीते छह साल में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ने देश की तस्वीर बदल दी है और सक्रिय गैस कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या दोगुनी से अधिक यानी 29 करोड़ हो गई है। रसोई गैस कनेक्शन भले आज हरेक के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन एक समय था कि यह एक खास वर्ग का 'स्टेटस सिंबल' हुआ करता था। सांसदों को हर साल 25 कूपन दिए जाते थे और वे अपने संसदीय क्षेत्र के 25 परिवारों में गैस कनेक्शन दिलवाकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। कनेक्शन की कालाबाजारी तो अक्सर सुर्खियां बनती थी। लेकिन अब सिर्फ पीएम-उज्ज्वला योजना के तहत ही गरीबों को 8 करोड़ कनेक्शन मुफ्त दिए जा चुके हैं। अगर कवरेज के लिहाज से देखा जाए तो 60 साल में जहां 55 फीसदी परिवारों तक एलपीजी पहुंची, वहां 6 साल में 43 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 99.6 फीसदी परिवारों तक पहुंच गई।

लेकिन पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने में जुटी मोदी सरकार के लिए देश भर में रसोई पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन को पहुंचाना आसान नहीं था। इसमें सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय संसाधनों की थी, जिसका

ईज ऑफ लिविंग क्रांतिकारी बदलाव

उज्ज्वला योजना ने भारत में जीवन सुगमता यानी 'ईज ऑफ लिविंग' के स्तर में क्रांतिकारी बदलाव किया है तो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से भी यह योजना बेहतरीन साबित हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स में भारत की बढ़ी हुई रैंकिंग इसकी गवाह है।

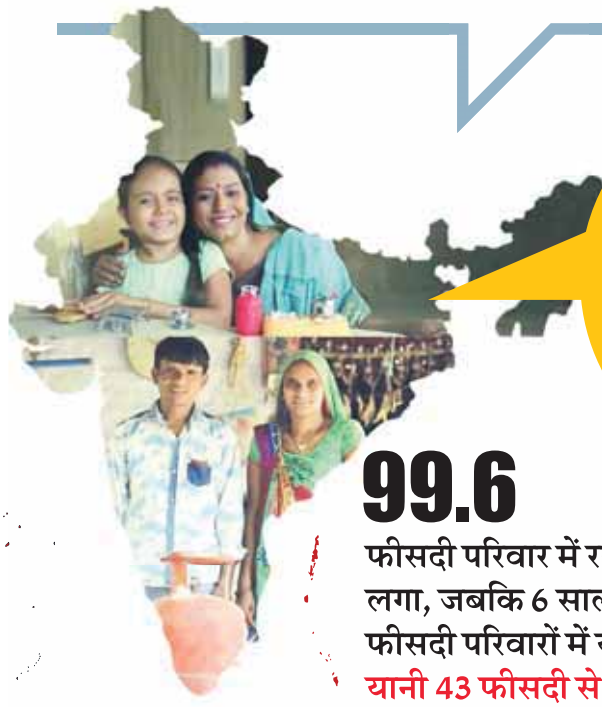

भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया। स्वच्छ ईंधन यानी गैस पर खाना बनाने वाले परिवारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में आई कमी।

99.6

फीसदी परिवार में रसोई गैस पर खाना बनने लगा, जबकि 6 साल पहले देश के सिर्फ 55 फीसदी परिवारों में यह सुविधा उपलब्ध थी। यानी 43 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई।

- महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय में बचत हुई और स्व-रोजगार के साथ-साथ परिवार में पुरुष के साथ-साथ महिलाएं भी रोजगार से आमदनी में सहयोग करने लगी।
- बच्चों और घर के कामकाजी पुरुष को समय पर भेजने में मदद मिली।
- लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अब जंगल में भटकने से मुक्ति मिली।

समाधान पूर्व की सरकारें भी कर सकती थीं। केंद्र सरकार के इस साहसिक निर्णय का नतीजा है कि इस योजना ने तय समय से 7 महीने पहले 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। जिसकी सराहना दुनिया भर में हो रही है। घाना-बांग्लादेश जैसे देश भारत की इस सफल योजना का अध्ययन कर उसे अपने यहां लागू भी कर रहे हैं। ऐसे में उज्ज्वला योजना के छह साल पूरे होने पर उसकी सफल यात्रा को भी समझना जरुरी है।

'पहल' से हुई पहल

मई 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सरकार की सोच में भी बदलाव दिखा। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाली एलपीजी व्यवस्था के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और रसोई गैस की सुविधा को पूरे भारत में बढ़ाने की नीति पर काम शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले सरकार ने डीजल की सब्सिडी खत्म कर उसे बाजार से लिंक किया। फिर सुखद संयोग बना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो पहले करीब 150 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थी, वो घटकर 26 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। इसके बाद आधार कार्ड की व्यवस्था को नीतिगत ढांचा देकर देश भर में फैलाया और 'जैम' यानी 'जनधन-आधार-मोबाइल' ट्रिनिटी की व्यवस्था

महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ने उज्ज्वला को सबसे बड़ी पहल माना है।

से 1 जनवरी 2015 को सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण (डीबीटीएल) की शुरुआत की गई। इसे 'पहल' नाम दिया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता बनी और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। इस डीबीटीएल से 4.11 करोड़ फर्जी कनेक्शन की पहचान कर 13 हजार करोड़ रुपये बचाए। लीकेज प्रूफ डिजिटल व्यवस्था ने सरकार को पूरे देश को रसोई गैस सुविधा से युक्त करने का वित्तीय आधार दिया।

पहल यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए इस योजना का जमीनी ढांचा तैयार करते वक्त ही इसका डिजिटल तंत्र तैयार कर लिया गया था, ताकि गरीबों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। उन्हें वितरक के पास

ग्लोबल हुई उज्ज्वला

- घाना और बांग्लादेश जैसे देश अपने यहां जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला जैसी योजना को लागू करने के लिए भारतीय उज्ज्वला योजना के मॉडल का अध्ययन कर चुके हैं।
- घाना ने इंडियन ऑयल के साथ इसके लिए समझौता किया है, क्योंकि घाना में सिर्फ 23 फीसदी आबादी के पास ही एलपीजी कनेक्शन है और लोगों को पेट्रोल पंपों पर लाइनों में लगकर सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं।
- उज्ज्वला योजना के जरिए धुआं मुक्त रसोई की पहल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2017 में वर्ल्ड पेट्रोलियम काउंसिल उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन, पेरिस ने उज्ज्वला की सफलता की कहानियों को अपनी वेबसाइट पर "Charting the Success of LPG distribuition in India" शीर्षक से प्रकाशित किया।
- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताकर भारत की प्रशंसा की।

जाकर सिर्फ इतना कहना था कि उन्हें उज्ज्वला का कनेक्शन चाहिए। उसके बाद की जिम्मेदारी पूरी तरह से वितरक की होती थी।

सक्षम वर्ग ने भी दिया समर्थन

जनता से जुड़ी योजना को जनता के सहयोग से जनता तक पहुंचाने की नीति मोदी सरकार के सुशासन का पर्याय है। इस योजना के लिए जमीनी ढांचा तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2015 को पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊर्जा संगम कार्यक्रम में 'गिव इट अप' की अपील की। उन्होंने संपन्न लोगों से एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया और कहा कि इस अभियान से जो पैसा बचेगा वह सरकार की तिजोरी में नहीं बल्कि गरीबों को दिया जाएगा। वहीं से उज्ज्वला योजना का ढांचा तैयार हो गया। प्रधानमंत्री के इस आह्वान में सक्षम वर्ग ने भी पूरा सहयोग दिया और देखते-देखते 1.08 करोड़ उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से गैस की सब्सिडी छोड़ दी। जब जनता ने साथ दिया तो उज्ज्वला सिर्फ कनेक्शन की बजाए जन आंदोलन और देश के गरीब-मध्यम वर्ग की जीवनधारा बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की।

24 घंटे सेवा, सोशल मीडिया के जरिए समाधान के साथ भुगतान, बुकिंग और रीफिल की सुविधा ऑनलाइन

आकांक्षाओं की उड़ान, जीवन हुआ सुगम

आम नागरिकों की नब्ज पकड़कर तैयार की गई और सफलता के परचम लहरा चुकी उज्ज्वला योजना एक ऐसा नीतिगत निर्णय साबित हुई है, जिसने गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति और खासकर महिलाओं के जीवन स्तर को बदल दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब शब्द नहीं, सरकार का मंत्र बन गया है जिसे साकार करने में उज्ज्वला योजना आधार स्तंभ बनी है। रसोई गैस पर खाना पकाने से बच्चों को स्कूल भेजना, घर के कामकाजी पुरुषों के लिए समय पर खाना पकाकर देना संभव हुआ तो महिलाओं के लिए अब रसोई घर से इतर अपने और परिवार के लिए समय निकाल पाना आसान हुआ है। इसकी वजह से खाली

स्वस्थ परिवार, स्वच्छ पर्यावरण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पारंपरिक ईंधन पर खाना पकाने से होने वाले प्रदूषण से हर साल भारत में 5 लाख लोगों की मौत हो जाती थी।
- अब डब्लूएचओ, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने पाया है कि उज्ज्वला की वजह से श्वास और फेफड़े से जुड़ी बीमारियों में 20 फीसदी की कमी आई है।
- खास तौर से नारी शक्ति के लिए उज्ज्वला ने बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया है।
- वनों की कटाई पर नियत्रंण हुआ, धुआं मुक्त रसोई ने सिर में दर्द, आंखों में जलन की समस्या से महिलाओं को दिलाई निजात।
- महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से रोजगार मिलने लगा, साथ ही रसोई में पूरा दिन की बजाए चंद घंटों में काम निपटने से पास-पड़ोस के लोगों के साथ सामाजिक परिचर्चा का भी वक्त मिलने लगा।
- गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदायों के जीवन को मजबूती मिली और सामाजिक सशक्तीकरण का आधार बना।

उज्ज्वला योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब 1 करोड़ नए गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य

समय का इस्तेमाल महिलाएं स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य कामों में सहजता से कर पा रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल कहते हैं, "भारत में 2020 तक सबको एलपीजी की सुविधा मुहैया कराना एक बड़ी उपलब्धि है। यह सिर्फ ऊर्जा पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक वित्तीय और सामाजिक पहल है।"

अगर जीवन की सुगमता के महत्व और इस योजना के पीछे देश के शीर्ष नेतृत्व की सोच को समझना है तो इस योजना की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के मन की पीड़ा को समझना होगा, जिसका इजहार उन्होंने कुछ इस तरह किया था, "मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारा जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी। आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना पकाती थी। कभी-कभी तो इतना धुआं होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे बचपन में धुएं में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं, बच्चों की पीड़ा को भलीभांति अनुभव करके आया हूं। उस पीड़ा को जी कर के आया हूं और इसलिए मुझे मेरी उन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। इसलिए 8 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का संकल्प लिया है।" इस योजना ने आम जन को स्वस्थ जीवन दिया है जो सेहतमंद समाज के निर्माण में भी सहायक साबित हो रही है।

स्वस्थ महिला, सशक्त समाज

वैज्ञानिकों का मानना है कि एक महिला जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता है। परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी इसका असर स्वाभाविक तौर पर पड़ता है। आंखों में जलन, सिर में दर्द, दमा, श्वास संबंधी बीमारियां आम होती हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना ने किस तरह से परिवार को स्वस्थ बनाकर एक सेहतमंद समाज के निर्माण में कदम बढ़ाया है उसका उदाहरण विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन चेस्ट सोसाइटी, चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन के आंकड़ों से मिलता है। पहले जहां 5 लाख मौतें सालाना इस पारंपरिक ईंधन

समाज के सभी वर्ग के गरीबों तक पहुंच

- जब उज्ज्वला योजना ने रफ्तार पकड़ी तो देश का शीर्ष नेतृत्व भी अलग मानस बना चुका था। पहले इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराना था। लेकिन इसकी बढ़ती महत्ता और लोगों के रूझान को देखते हुए 2018 में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया।
- पहला लक्ष्य 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया था। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा हुआ तो इसमें अन्य कैटेगरी भी जोड़ी गई।
- सामाजिक आर्थिक जनगणना के अलावा इसमें सभी एससी/एसटी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, चाय बागान के जनजाति, द्वीपों पर रहने वाले लोग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण आदि को भी इसमें शामिल किया गया।
- अभी तक 8 करोड़ लाभार्थियों में से अकेले एससी-एसटी वर्ग से 3.05 करोड़ यानी 38 फीसदी से अधिक आबादी है। इतना ही नहीं, रसोई गैस की सुविधा पहुंचाना भर ही सरकार की सोच नहीं है। सरकार की मंशा रसोई गैस की उपलब्धता को विस्तार देना है ताकि लोग दूरी की वजह से इसका इस्तेमाल बंद न करे।
- आपूर्ति की सेवा को बढ़ाने के लिए गैस वितरकों की संख्या बढ़ाने के लिए जियो टैगिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया और 15 किमी के दायरे में नए वितरक बनाए।
- पहले 13,500 एलपीजी वितरक थे जो अब 25 हजार से अधिक हो गए हैं। इसका लाभ खासतौर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को मिला है जहां पहले उपभोक्ता और वितरक दोनों ही कम थे।

एलपीजी का आयात भी 16 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 26 मिलियन मिट्रिक टन किया गया है।

- इसके अलावा एक बड़ी चुनौती इस योजना में थी कि 14 किलो के सिलेंडर के लिए 800 रुपये की रकम कैसे एक गरीब देगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे पसंद नहीं किया।
- सरकार ने कनेक्शन लेते वक्त लोगों को 1600 रुपये का लोन दिया था जो सब्सिडी के जरिए काटा जाना था। लेकिन लोगों को रिफिलिंग में दिक्कत नहीं हो इसलिए सरकार ने अपनी ओर से हर कनेक्शन पर इस 1600 रुपये के लोन को आगे बढ़ा दिया है, जिस पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा।

वाली रसोई से हुआ करती थी, लेकिन अब श्वास संबंधी बीमारियों को 20 फीसदी तक कम करने में उज्ज्वला योजना ने अहम भूमिका अदा की है। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह योजना कारगर साबित हो रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के प्रो. एस.के. बरुआ ने क्षेत्रों में जाकर किए अपने अध्ययन में माना है कि एलपीजी की वजह से घरों में होने वाले प्रदूषण में भारी कमी आई है, जिसका स्वाभाविक लाभ महिलाओं-बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक बिरोल भी कहते हैं कि घरों से प्रदूषण दूर हो रहा है। पारंपरिक ईंधनों से पैदा होने वाले मिथेन, ब्लैक कार्बन और ऑर्गेनिक कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उसमें कमी आ रही है। वनों की कटाई में भी कमी की बात यूएन मल्टी-डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कही गई है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में भी उज्ज्वला योजना एक स्तंभ बनकर उभरी है। ऊर्जा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग दो पायदान चढ़कर 74 आ गई। वहीं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के टॉप-10 परफॉर्मर में भारत 10वें नंबर पर आ गया है। वर्ष 2014 में यह रैंकिंग 31वीं थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2018 से लगातार इस योजना की तारीफ कर रहा है। इस संगठन का कहना है कि जब दुनिया के अन्य देशों में वायु प्रदूषण की समस्या खतरनाक हो रही है, भारत ने इसमें सकारात्मक संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर घरों में स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित किया है।

कोरोना काल और भविष्य की राह

कोरोना जैसी आपदा में उज्ज्वला योजना ने किस तरह से गांव-गरीब को

पंचायत और पांच मंत्र

उज्ज्वला को सफल बनाने के लिए किए गए इन प्रयासों को सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व के घरों तक एलपीजी पंचायत का आयोजन कर इसकी महत्ता को विस्तार दिया गया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग पर भी कल्याण की इस योजना ने नया आकार लिया। इस योजना से लोग जुड़ें और इसका निरंतर प्रयोग भी करें, इस लक्ष्य के साथ योजना की शुरुआत के करीब एक साल बाद अक्टूबर 2017 में एलपीजी पंचायत की अनोखी अवधारणा पर काम हुआ। इसके पांच अहम उद्देश्य थे-

वैसे तो समय को कोई खरीद नहीं सकता,लेकिन उज्ज्वला से ऐसा लगता है कि जैसे हमने समय ही खरीद लिया है।

राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एलपीजी पंचायत में लाभार्थी नारायणी साहू

इस पंचायत का मकसद स्वच्छ ईंधन का निरंतर प्रयोग और सुरक्षा की चिंताओं का निपटारा करना था। इस पंचायत की थीम थी- 'कुछ सीखें, कुछ सिखाएं'। गुजरात से शुरू हुई पहली पंचायत के बाद से अब तक देश में सवा लाख इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जा चुका है।

सुरक्षा एवं कुशलता: सुरक्षित, तत्काल व भरोसेमंद सहायता।

स्वास्थ्य: धुआं रहित घर में खाना बनाने की सुविधा के फायदे।

पर्यावरण: वायु प्रदूषण में कमी के साथ वन व भूमि संरक्षण।

आर्थिक विकास: सस्ते ईंधन के कारण कैसे आय के बेहतर अवसर मिलेंगे।

सशक्तीकरण: जीवन स्तर में सुधार।

संभाला, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गरीब कल्याण पैकेज। जब देश में लॉकडाउन लगा तो गरीबों के घर का चूल्हा बंद नहीं हो, इसके लिए सरकार ने अन्न योजना के साथ-साथ खाना पकाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया। कोरोना काल में 9600 करोड़ रु. खर्च कर सरकार ने 14.17 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में गरीबों को दिए।

उज्ज्वला योजना इतनी सफल हुई और समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा किया तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि यह सीधे केंद्र सरकार द्वारा सोची, तैयार की गई और जमीन पर साकार की गई योजना थी, जिसमें पूरी मशीनरी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में चल रही थी। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मातहत तेल कंपनियों ने देश के 750 जिलों में जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) तैनात किए। इन युवा अधिकारियों से पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हर सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग से संवाद करते थे, ताकि मनोबल भी बढ़ाया जा सके और योजना के क्रियान्वयन की सीधी निगरानी भी हो सके। एक निर्धारित लक्ष्य और उसके प्रति समर्पण ने उज्ज्वला योजना को स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा में सुधार का ऐसा पर्याय बना दिया कि दुनिया भी उसकी मुरीद हो गई।

निश्चित तौर से उज्ज्वला योजना की सफलता अपनी कहानी खुद बयां कर रही है, लेकिन सरकार ने थमने का नाम नहीं लिया है। एलपीजी कवरेज को 99.6 फीसदी तक पहुंचा चुकी केंद्र सरकार ने इस बार के आम बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है ताकि शहरों में छूटे हुए वे वर्ग जिनका कोई स्थायी पता नहीं होता या घुमंतू होते हैं, ऐसे 0.4 फीसदी लोगों की पहचान कर उन्हें रसोई गैस कनेक्शन देना है। यही वजह है कि दीर्घकालिक सोच के साथ बनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम योद्धा के तौर पर दिख रही है। ●

बातचीत

कॉरपोरेट पहचान वाले पेट्रोलियम मंत्रालय को उज्ज्वला योजना ने लोगों से जोड़ दिया

गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश.. मेरा देश.. मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।" नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दो साल पूरा होने पर बनाया गया 2.46 मिनट का यह गीत जनता की जुबां पर है, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जाता है। इस योजना ने देश और दुनिया के लिए सामाजिक सशक्तीकरण की अद्भुत मिसाल पेश की है। 1 मई को इस योजना के छह साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए न्यू इंडिया समाचार के सलाहकार संपादक संतोष कुमार ने केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की। पेश है अंशः

> मैं तो इतना ही कहूंगा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहचान पहले सिर्फ कॉरपोरेट जगत से जुड़ी मानी जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इसे नया अर्थ दिया है और इसे आर्थिक निवेश से सामाजिक बदलाव का अग्रदूत बना दिया है। उज्ज्वला ने ऊर्जा नीतियों में महिलाओं को केंद्र बिन्दु पर ला दिया है।

Q उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार ने क्या कोई ऐसा अध्ययन किया था कि जो लोग केरोसिन, उपले, लकड़ी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करते हैं, उन्हें एलपीजी की जरूरत है। आखिर सरकार की क्या सोच थी?

A इसका जवाब मैं एक लाभार्थी के शब्दों से दूंगा। 2017 में बिहार के दरभंगा के छतरिया गांव की एक उज्ज्वला लाभार्थी फूलो देवी ने कहा था, "अब गैस दरवाजे तक आती है, पहले ऐसा कहां सोच सकते थे गांव में।" अक्सर मुझे रसोई के स्वच्छ ईंधन पर काम करने वाले विशेषज्ञ पूछते हैं, ऐसी पहल के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। कई दशकों तक गांव-देहात के लिए नए वैकल्पिक चूल्हों पर काम किया गया। लेकिन मुझे लगता है जो सहजता, सुलभता एलपीजी से खाना पकाने में है, वो किसी और विकल्प में नहीं है। एलपीजी ने गरीब महिलाओं की आकांक्षा पूरी की। देश की आजादी के इतने वर्षों तक रसोई गैस को वर्ग विशेष की वस्तु बनाकर रखा गया, जबकि देश के संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार है। अब हमने 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है और 60 साल में जहां 55 फीसदी परिवारों तक 13 करोड़ कनेक्शन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट विजन की वजह से सिर्फ 6 साल में एलपीजी धारक परिवारों की संख्या दोगुनी से ज्यादा होकर 29 करोड़ तक पहुंची है और 99.6 फीसदी परिवार इसके दायरे में आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ शहरी गरीब हैं जो छूट गए हैं। खासतौर से एड्रेस प्रूफ की कमी आदि से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 में हमने उन सभी शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखा है। इसके क्रियान्वयन की पूरी प्रणाली जल्द ही हम देश के सामने रखेंगे।

Q योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन किसी योजना का क्रियान्वयन अहम होता है। ऐसे में सीधे केंद्र सरकार की ओर से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया गया और यह कितना चुनौतीपूर्ण था?

A मेरी समझ से पहल योजना ने इसकी नींव रखी, जिसने हमें नई सोच के साथ एलपीजी की पहुंच सभी तक करने की दिशा में काम करने का मौका दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह विभिन्न तरीके से सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का काम हुआ और गिव इट अप अभियान में संपन्न वर्ग ने भी जिस ऊर्जा के साथ गरीबों के घरों तक ऊर्जा पहुंचाने की इच्छाशक्ति दिखाई, उससे सरकार का भी हौसला बढ़ा। यही वजह है कि उज्ज्वला योजना ने अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई। यह बात भी सही है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इतनी बड़ी योजना को जमीन पर तय समय में साकार करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। गैस की सप्लाई बढ़ाने से लेकर बोटलिंग प्लांट, सिलिन्डर बनाने, रेग्युलेटर, सुरक्षा होज, गैस चूल्हे सभी कुछ की सप्लाई पर हमने काम किया। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक मेरे स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों के फोकस में कोई कमी नहीं आई है। गरीब की पीड़ा को मोदी सरकार महसूस करती है इसलिए समय-समय पर इस योजना से जुड़ी समस्याओं के लिए भी तत्काल समाधान की दिशा में कई बदलाव किए गए।

Q गांवों में एलपीजी की रिफिलिंग की समस्या थी क्योंकि वितरक बहुत दूर हुआ करते थे, उस समस्या को सरकार ने किस तरह से दुरुस्त किया?

A आप वितरकों के आंकड़े देखिए, करीब 10 हजार से अधिक नए वितरक सेवा में आए है। उज्ज्वला के कारण एलपीजी कनेक्शन की संख्या बढ़ी है। जिससे वितरकों को भी व्यावसायिक लाभ हुआ है। जन सुविधा केंद्र और उज्ज्वला दीदी की पहल से भी इस सेवा में सुधार की उम्मीद है।

Q सिलेंडर में एकमुश्त राशि देनी पड़ती है जो आमतौर से कुछ गरीबों के लिए आसान नहीं होता है, सरकार ने उसके लिए क्या किया है और भविष्य की क्या योजना है?

A देखिए, उज्ज्वला योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य हर घर तक एलपीजी की पहुंच को सुनिश्चित करना था। इसी बीच में रिफिलिंग की समस्या आई तो हमने छोटे सिलेंडर के विकल्प पर भी काम किया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने 14 किलो वाले सिलेंडर को ही प्राथमिकता दी। आपको याद होगा कि उज्ज्वला के तहत 1600 रूपये का लोन भी उपभोक्ताओं को दिया गया था जो सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी से लिया जाना था। लेकिन गरीबों पर कोई बोझ नहीं पड़े और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार ने उस लोन को भी आगे बढ़ा दिया है।

Q कोरोना जैसे संकट के दौरान गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से राहत प्रदान करने में उज्ज्वला कितनी सहायक हुई?

A आपने देखा होगा कि जब देश लॉकडाउन की ओर जा रहा था। केंद्र सरकार ने स्पैनिश फ्लू के समय की परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया था। जिसके आधार पर लॉकडाउन के अगले दिन ही 1.75 लाख करोड़ रु. की गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई। दृष्टिकोण बेहद साफ था कि लॉकडाउन की स्थिति में किसी गरीब के घर का चूल्हा न बुझे। सरकार ने तय किया कि उज्ज्वला के तहत तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार ने गरीबों के लिए 9600 करोड़ रु. का आर्थिक बोझ अपने ऊपर रखा और गरीब के घरों तक 14 करोड़ से अधिक सिलेंडर पहुंचाए। देश बल्कि पूरा विश्व एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। ऐसे में पब्लिक फाइनेंस का भी बहुत दबाव है। नियमित रुप से लोग स्वच्छ ईंधन ही इस्तेमाल करे इस पर अभी चहुमुंखी प्रयासों की जरूरत है।

Q घाना समेत विश्व के कई देशों ने उज्ज्वला पर भारत से विशेषज्ञता सहयोग मांगा है, आपकी क्या तैयारी है?

A यह भारत की बदलती सोच का उदाहरण है। दुनिया देख रही है कि भारत जब नई ऊर्जा और नई सोच के साथ कदम उठाता है तो उसे सफल बनाकर ही रुकता है। उज्ज्वला के माध्यम से हमने जिस तरह गरीबों को लक्ष्य से पहले रसोई गैस पहुंचाई और उन्हें प्रेरित किया कि स्वच्छ ईंधन उनके लिए कितना फायदेमंद है। इसी सोच ने दुनिया को भी भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर किया है। आज दुनिया के ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य से जुड़े अध्ययनों को देख लीजिए, हर जगह उज्ज्वला योजना की सफलता की कहानियां लिखी जा रही है। ●

Q&A

महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों और पर्यावरण संरक्षण को कम करने में कितनी मदद मिली है?

इस बारे में एक मंत्री से ज्यादा विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन, चेस्ट सोसाइटी फाउंडेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईआईएम अहमदाबाद, वर्ल्ड पेट्रोलियम काउंसिल और देश-दुनिया की कई यूनिवर्सिटी के अध्ययनों में यह बात साफ तौर से आई है कि रसोई के धुआं मुक्त होने से प्रदूषण जनित बीमारियों में कमी आई है। फेफड़े, सांस संबंधी बीमारियों आदि में कमी आई है। इस योजना से वनों की कटाई में कमी हुई है। उज्ज्वला योजना से कैसे रसोई में काम करने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को लाभ मिला है, ये बातें देश-दुनिया के अध्ययन में सामने आई हैं।

पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संपूर्ण विकास संभव

भारत का स्वर्णिम युग तब था जब पूरब ही पूरे भारत का नेतृत्व करता था। चाहे ओडिशा हो या बिहार या कोलकाता, ये भारत का नेतृत्व करने वाले केंद्र बिंदु थे। उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण महताब की पुस्तक- 'ओडिशा इतिहास' के हिंदी रुपांतरण के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश आजादी के इतिहास से सीख लेकर युवा सामर्थ्य के साथ बना भारत को ऊंचाईयों पर ले जाने का युवा संकल्प

"भारत का संतुलित विकास नहीं होता है तो शायद हम हमारी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि जैसे भारत के पश्चिमी भाग में इन दिनों प्रगति, समृद्धि, आर्थिक प्रगति नजर आएगी। लेकिन पूरब में जहां इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, अद्भुत मस्तिष्क है, मानव संसाधन हैं। ओडिशा, बिहार, प. बंगाल, असम समेत पूर्वोत्तर में एक ऐसी अद्भुत सामर्थ्य की पूंजी पड़ी है, अगर अकेला ये इलाका ही विकसित हो जाए तो हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रह सकता।" यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पिछले छह साल में पूर्वी भारत के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, ताकि देश का एक संतुलित विकास हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण महताब की पुस्तक के हिंदी अनुवाद के विमोचन के मौके पर पूर्वी भारत के विकास के प्रति अपना संकल्प दोहराया।

फिर निश्चय से विजय होगी, उत्कल भूमि की जय-जय होगी

उत्कल जननी ने हमेशा ऐसे महामानवों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू से सींचा और आजादी के फूल खिलाए। उन्हीं में से एक थे- उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण महताब

भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि, कला-संस्कृति की जन्म स्थली, वीरों और महापुरुषों की जननी है ओडिशा। कलिंग राज्य का उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है। इसकी कहानी वे पत्थर भी कहते हैं जिन पर यहां के प्रतापी सम्राट खारवेल का नाम लिखा है। ओडिशा के निवासी कितने स्वाभिमानी, राष्ट्रभक्त और साहसी हैं, इस बात का प्रमाण कलिंग युद्ध स्वयं है। शक्तिशाली सम्राट अशोक की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर कलिंग की संतानों ने युद्ध में गौरवशाली मृत्यु को गले लगाया था और यहीं से सम्राट अशोक से वे धम्म अशोक बन गए थे। जब भारतीय उपमहाद्वीप को अंग्रेजी शासन का ग्रहण लगा तो पहली प्रखर ललकार यहीं से सुनाई दी। वर्ष 1804 में जयी राजगुरू (जयकृष्ण महापात्र) और 1817 में बख्शी जगबंधु (जगबंधु विद्याधर महापात्र), चकरा बिसोई, रेंडो माझी के नेतृत्व में हुआ सशस्त्र पाइक संग्राम, विदेशी आतताईयों पर हुआ पहला आघात था। बाद में सरदार सुरेंद्र सांईं ने मुक्ति संग्राम को आगे बढ़ाया। मधुसूदन दास और गोप बंधु ने सत्याग्रह की राह पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया, वहीं लक्ष्मण नायक, बालक बाजी राउत और रघु दिवाकर जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहूति देकर मातृभूमि का कर्ज चुकाया। पबित्र मोहन प्रधान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश का मान सुरक्षित रखा।

आधुनिक ओडिशा की नींव रखने वाले डॉ. महताब

जब अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वालों की बात चलती है तो सहज ही नाम याद आ जाता है उत्कल केसरी डॉ. हरेकृष्ण महताब का। जब देश ने सहायता के लिए पुकारा तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर युवा हरेकृष्ण ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठ खड़े हुए। 23 अप्रैल 1946 में वे आजादी से पहले ओडिशा के प्रधानमंत्री बनें और फिर अपने प्रयासों से उन्होंने 25 रियासतों का एकीकरण वृहत्तर ओडिशा का गठन किया था। जिसमें सरदार पटेल का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। बाद में वे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉ. महताब अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका किरदार और भी बुलंद था। उन्होंने न सिर्फ नव ओडिशा की सीमाओं का ही निर्धारण किया बल्कि उसके भविष्य के लिए सपने भी देखे और निर्माण भी किए। उन्होंने हीराकुंड बांध के निर्माण, पारादीप बंदरगाह, राउरकेला स्टील प्लांट सहित अनेक उद्योगों की स्थापना से आधुनिक ओडिशा की नींव रखी तो कटक के स्थान पर भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाई। उत्कल इतिहास को राष्ट्रीय मंच तक ले जाने में महताब जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओडिशा में बने संग्रहालय, अभिलेखागार या पुरातत्व खंड यह सब उनकी दृष्टि और योगादन से ही संभव हुआ है। मजबूत बुनियाद पर खड़ा ओडिशा आज धामरा और पारादीप बंदरगाह का कायाकल्प हो या ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना, खनिजों का सही उपयोग हो या फिर प्रदेश को हाइड्रोकार्बन हब बनाने की बात, ओडिशा अपने नवोदय की ओर निरंतर बढ़ रहा है, आज ओडिशा प्रेरित भी है और सक्षम है। डॉ. महताब ने ओडिशा के वृहद इतिहास की रचना की। जिसके हिंदी संस्करण का विमोचन 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर महत्वपूर्ण बात कही कि भारत का इतिहास सिर्फ राजमहलों का इतिहास नहीं है। जन-जन के जीवन के साथ इतिहास का अपने आप निर्माण हुआ है, तभी तो हजारों साल की इस महान परंपरा को लेकर हम जिये होंगे। ये बाहरी सोच है कि जिसने राजपाट और राजघरानों के आसपास की घटनाओं को ही इतिहास मान लिया। हम वो लोग नहीं हैं। पूरी रामायण और महाभारत को देखिए, उसमें 80 प्रतिशत बातें सामान्य जन की हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में जन सामान्य एक केंद्र बिंदु में रहा है। आज हमारे युवा इतिहास के उन अध्यायों पर शोध कर रहे हैं और उन्हें नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रयासों से कितनी प्रेरणाएं निकलकर सामने आएंगी, देश की विविधता के कितने रंगों से हम परिचित हो पाएंगे।

पूर्वी भारत के विकास को गति

व्यापार और उद्योगों के लिए सबसे पहली जरूरत है- इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिशा में हजारों किमी के नेशनल हाईवेज, कोस्टल हाइवेज बन रहे हैं जो बंदरगाहों को आपस में जोड़ेंगे। सैकड़ों किमी नई रेल लाइन पिछले 6-7 सालों में बिछाई गई हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्वपूर्ण घटक है उद्योग। इस दिशा में उद्योगों, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम हो रहा है। तेल और गैस से जुड़ी जितनी व्यापक संभावनाएं ओडिशा में मौजूद हैं, उनके लिए भी हजारों करोड़ का निवेश किया गया है। इसी तरह स्टील इंडस्ट्री की व्यापक संभावनाओं को भी आकार दिया जा रहा है। ओडिशा के पास समुद्री संसाधनों से समृद्धि के अपार अवसर भी हैं। देश का प्रयास है कि नीली क्रांति के जरिए ये संसाधन ओडिशा की प्रगति का आधार बनें, यहां के मछुआरों-किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो। ओडिशा के युवाओं को इस विकास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएसईआर बहरामपुर और कौशल विकास जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है। इसी साल जनवरी में ओडिशा में आईआईएम सम्बलपुर का शिलान्यास किया गया है जो आने वाले वर्षों में ओडिशा के भविष्य का निर्माण कर विकास को नई गति देगा।

निश्चित तौर से ओडिशा का इतिहास समूचे भारत की ऐतिहासिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि ओडिशा का व्यापक और विविध इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे। ●

पोखरण: जब दुनिया ने देखी भारत की शक्ति

कोई काम किया गया सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार महत्वपूर्ण यह होता है कि वह कैसे किया गया... आज से ठीक 23 साल पहले 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण में भी यही हुआ था। यूं तो भारत इससे पहले भी 18 मई 1974 को परीक्षण कर चुका था, लेकिन मई 1998 वो वक्त था जब दुनिया के तमाम देश हमारी निगरानी में लगे थे। इसके बावजूद 5 परमाणु परीक्षण कर तबकी केंद्र सरकार ने अपनी ताकत ही नहीं, सामर्थ्य और राजनैतिक इच्छाशक्ति का अहसास दुनिया को कराया, जिसको उस वक्त शपथ लिए हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे...

भारत ने 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के सिद्धांत पर चलते हुए हमेशा से ही वैश्विक शांति को अपना ध्येय बनाया है। लेकिन जब बात आत्मसुरक्षा और सम्मान की हो, देश ने किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। पोखरण इसी आत्मसम्मान और गौरव गाथा का नाम है, जहां 18 मई 1974 को देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का रास्ता तैयार हुआ तो 11 मई 1998 का दिन इस महायज्ञ के लिए पूर्णाहुति साबित हुआ। दरअसल, ये कहानी परमाणु क्षमता में आत्मनिर्भर बनने की भारत की उस शुरुआत की है, जिसकी तैयारी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में अपनी 13 दिन की सरकार के दौरान कर ली थी। हालांकि तब सरकार गिरी तो योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।

11 मई 1998 की तपती दोपहर। वक्त दोपहर करीब 3.45 बजे। प्रधानमंत्री का तब का आधिकारिक आवास 7 रेस कोर्स रोड। थोड़ी देर बाद लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। हालांकि परंपरा के विपरीत तब तक किसी को इसका विषय नहीं मालूम था। तभी कैमरों के सामने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोलना शुरू किया- "आज, 3.45 बजे, भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए. आज एक फिशन, एक लो यील्ड डिवाइस और एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के साथ परीक्षण किए गए।"

> **"ये भारत बदला हुआ भारत है। दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। ये किसी प्रतिबन्ध के आगे झुकेगा नहीं। हमारे परमाणु हथियार किसी देश के खिलाफ नहीं, शांति और सुरक्षा के लिए हैं। -अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री (परीक्षण के बाद संसद में बोलते हुए)"**

ये शब्द भारत को दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के सामने एक सशक्त

तमाम देशों की निगरानी के बीच कैसे सफल हुआ भारत...

भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए इसे ऑपरेशन 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम दिया गया था। मई 1998 में हुए परीक्षण को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'ऑपरेशन शक्ति' नाम दिया। उस वक्त की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस ऑपरेशन के पीछे की तैयारियों का जिक्र कुछ इस तरह है...

- इससे पहले सन 1995 में भारत ने परमाणु परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद पोखरण की निगरानी कम करने की बजाए बढ़ा दी गई। चार सैटेलाइट लगातार इस जगह पर नजर रखे हुए थे।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी निगरानी सैटेलाइट से बचने के लिए उनकी रियल टाइम गतिविधि का पता लगाया। आखिरकार वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल रहे कि ये सैटेलाइट पोखरण के रेतीले इलाकों के ऊपर से कब गुजरते हैं और कब वापस आ जाते हैं।
- पोखरण की परीक्षण रेंज पर 24 घंटे में 2 या 3 बार सैटेलाइट की नजरें जाती थीं। ऐसे में इससे बचने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने इस समय कोई भी काम नहीं किया।
- इस प्रॉजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि वे एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को छद्म नामों से बुलाते थे। उस दिन सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया था ताकि खुफिया एजेंसी को यह लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं।
- गोपनीयता का आलम यह था कि मेजर जनरल की वर्दी में नटराज लिखी नेम प्लेट में परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष आर चिदंबरम, मेजर जनरल पृथ्वीराज की यूनिफॉर्म में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सेना की वर्दी में ही परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकर और संथानम भी परीक्षण स्थल पर मौजूद थे।
- 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को 'ऑपरेशन शक्ति' नाम दिया गया। तड़के करीब 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इसे मुंबई से भारतीय वायु सेना के प्लेन से जैसलमेर बेस लाया गया था।
- ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कुछ इस तरह से बातें की जाती थीं, जैसे- क्या स्टोर आ चुका है? परमाणु बम के एक दस्ते को 'ताजमहल' कहा जा रहा था। अन्य कोड वर्ड्स थे वाइट हाउस और कुंभकरण।
- वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिन पर मोटे-मोटे तार निकले हुए थे।
- 13 मई को जब परीक्षण किया गया तो धमाके से आसमान में धुएं का गुबार उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था।

राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की शुरुआत थी। भारत को 'नया भारत' बनाने के इसी मार्ग पर आज देश एक बार फिर अग्रसर है। अटल जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 45 घंटे बाद 13 मई को पोखरण में दो और शक्तिशाली बमों का परीक्षण किया गया। इसके बाद से ही 11 मई के दिन देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए थे, वह महत्वपूर्ण है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। तब भारत की शक्ति के लिए अटल जी ने जय जवान, जय किसान के साथ जो 'जय विज्ञान' का हमें मंत्र दिया, उसे आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत बनाने के लिए, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समर्थ भारत बनाने के लिए हर युवा योगदान देने का संकल्प करे। अपने सामर्थ्य को भारत के सामर्थ्य का हिस्सा बनाए।" पोखरण में परमाणु परीक्षण के साथ ही उस समय दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश बन गया, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दुनिया के तमाम देशों ने भारत के परीक्षणों की कड़ी आलोचना की। हम पर कड़े प्रतिबंध तक लगा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भारत ने वो मुकाम हासिल किया जिसे याद कर हर देशवासी का सीना आज भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। कभी साहसिक फैसलों से दुनिया को चकित करने वाले तो कभी हल्के-फुल्के अंदाज में लोगों से संवाद कर आम जन के दिलों के रत्न बन चुके अटल जी को 2014 में उन्हीं की राह पर चलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। ●

जन सुरक्षा से जीवन रक्षा

क्या आपके मन में भी अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके बाद परिवार का आर्थिक भविष्य क्या होगा? या फिर आपके मन में यह सवाल तो नहीं कि बुढ़ापे में आपकी आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी होंगी? इन सभी सवालों का जवाब हैं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन जैसी योजनाएं...

> **"सभी योजनाओं के मूल में दो बातें अहम हैं- पहला कि सभी को बीमा कवर मिले और कम से कम प्रीमियम पर मिले, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है, गरीबों के कल्याण को महत्व देती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।**
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री"**

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की कांता देवी के पति का कुछ दिन पहले निधन हो गया। इस मुश्किल घड़ी में उनके सामने आर्थिक संकट भी था, लेकिन अपने जीवन काल में कांता के पति ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले रखी थी। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कांता के खाते में दो लाख रुपये डाल दिए गए। कांता कहती हैं, "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से मुश्किल वक्त में मदद मिली है। यह बहुत अच्छी योजना है।"

कांता से थोड़ा सा हटकर कहानी सुनीता की भी है। बुजुर्ग होने पर आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े इसलिए सुनीता ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी है। सुनीता कहती हैं, "भविष्य किसके सहारे कटेगा? यह सवाल मन में था। मेरी कोई पॉलिसी नहीं

- साल में सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का बीमा मिल जाता है और इसके लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है।
- यह योजना 18 -50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। इस टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है और यह 55 साल की उम्र में मैच्योर होता है।
- किसी भी बैंक की शाखा में जाकर या घर से ही नेट बैंकिंग के जरिए यह बीमा ले सकते हैं। आप इस स्कीम के पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

2.93 करोड़ नाम दर्ज अटल पेंशन योजना में

10.06 करोड़ नाम दर्ज जीवन ज्योति बीमा योजना में

22.73 करोड़ नाम दर्ज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में

आंकड़े 28 फरवरी 2021 तक

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इस बीमा का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति साल भर में **12** रुपये का प्रीमियम भरकर **02** लाख रुपए तक का बीमा करवा सकता है।

- यह एक दुर्घटना पॉलिसी है जिसके तहत किसी दुर्घटना में मौत या स्थायी दिव्यांगता के लिए दो लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता में 1 लाख रुपए का कवरेज मिलता है।
- 18 साल से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति यह बीमा करवा सकता है। बीमित व्यक्ति के 70 साल के होने पर यह बीमा खत्म हो जाएगा। इस योजना के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है।
- प्रीमियम कटने के दौरान खाते में बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी खुद ही रद्द हो जाएगी। बैंक खाता बंद होने पर भी पॉलिसी रद्द मानी जाएगी।

अटल पेंशन योजना

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 वर्ष तक निवेश करना होता है। यह निवेश 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
- 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस के अंतर्गत 1000, 2000, 3000 और 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
- पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने प्रतिमाह कितने प्रीमियम का भुगतान किया है और किस उम्र से निवेश करना आरंभ किया है।

अटल पेंशन योजना की शुरूआत के पहले दो वर्षों के दौरान, लगभग 50 लाख ग्राहकों के नाम दर्ज किए गए थे जो तीसरे वर्ष में दोगुने होकर 1 करोड़ हो गए और चौथे वर्ष में यह संख्या 1.50 करोड़ पर पहुंच गई। 2019 के वित्तीय वर्ष में योजना के तहत लगभग 70 लाख ग्राहकों के नाम दर्ज किए गए थे।

थी। इसलिए जैसे ही इस योजना के बारे में पता चला तो मैंने इसे ले लिया। अब मैं सबसे बोलने लगी कि यह बहुत जरूरी है।"

कांता और सुनीता जैसे करोड़ों लोग आज केंद्र सरकार की इन योजनाओं की बदौलत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाए हैं। दरअसल, इस योजना के शुरु होने से पहले तक देश में 80 से 90 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं था। जिन्हें किसी तरह की पेंशन मिलने की संभावना नहीं थी। देखा जाए तो 12 रुपए बहुत ही मामूली रकम होती है लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इन्हीं 12 रुपए में दो लाख रुपए के इंश्योरेंस की स्कीम शुरु की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में गरीबों को बीमा का लाभ देने के लिए सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरु की थी। ●

परंपरा को मिली पहचान, हुनरमंद हाथ को हौसला

केंद्र सरकार का उद्देश्य विकासोन्मुख क्षेत्रों से जुड़े अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों को बड़े बाजार नेटवर्क का हिस्सा बनाना है। ऐसे समुदाय को ध्यान में रख छह साल पहले शुरू की गई (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फॉर डवलपमेंट- USTTAD) हस्तशिल्पियों और पारंपरिक दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए साबित हो रही है लाभकारी...

भारत अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है तो अल्पसंख्यक समुदायों को उनके पारंपरिक कौशल, कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धी बाजार वैश्वीकरण, मास्टर कारीगरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से ये कौशल युवा पीढ़ी द्वारा नहीं अपनाए जा रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने कुटीर और लघु उद्योग की रीढ़ मानी जाने वाली पारंपरिक कला और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उसकी ब्रांडिंग के मकसद से एक ऐसी योजना की शुरुआत छह साल पहले की थी, जिसे 'उस्ताद' नाम दिया गया। 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने मूल मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 14 मई 2015 को वाराणसी में उस्ताद योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों, हस्तशिल्पियों और पारंपरिक कलाकारों की प्रतिभा को सही पहचान दिलाना और नए वक्त के साथ उनकी कला को निखारने का है। इस योजना के तहत कारीगरों को अपने काम से जुड़ी नई जानकारियां और ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, बल्कि इसमें सभी जाति और मजहब के लोग शामिल हैं।

योजना से संबंधित सभी जानकारी उस्ताद योजना पोर्टल और www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

- इसमें शिल्पकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कौशल विकास के साथ-साथ उनके उत्पादों की बिक्री में भी मदद की जाती है।
- उस्ताद योजना में 45 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को किसी भी तरह की कुशलता (03 से 08 महीने तक) सीखने के लिए सरकार हर महीने 3000 रुपये देती है। पहले इसमें उम्र की सीमा 14 से 35 साल थी। इस योजना में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
- उस्ताद योजना के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में से 33 पारंपरिक कलाओं को सिखाने का उद्देश्य रखा गया है। जैसे- उत्तर प्रदेश से चिकनकारी और कांच का काम, जम्मू कश्मीर से पेपरमशी, पंजाब से फुलकारी, राजस्थान से लहरिया और गुजरात से अजरक के काम को चुना गया है।
- अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों शिल्पकारों को आगे बढ़ाने, उनके क्षमता निर्माण और उन्नयन के लिए इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों और इसी तरह के क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध संगठनों और संस्थानों की मदद ले रहा है। ●

महापराक्रमी महाराणा

भारत का इतिहास ऐसे कई शूरवीरों से भरा हुआ है, जिनकी वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन कुछ वीर ऐसे भी हैं, जिनके नाम से ही वीरता के किस्सों की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने जमीन पर सोना और घास की रोटी खाना मंजूर किया पर किसी की गुलामी को स्वीकार कर आत्मसम्मान नहीं खोया। अपने अंतिम समय तक मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा करते रहे और ऐसे किस्से छोड़ गए, जिनका उदाहरण दिए बगैर आज भी देश प्रेम, त्याग बलिदान और आजादी के मायने ही अधूरे हैं...

इतिहास दो तरह का होता है। एक जो शिलालेखों, सरकारी रोजनामचों में दर्ज होता है और जिसे किताबों में पढ़ाया जाता है। दूसरा, जो लोगों की स्मृति में दर्ज होता है, जिसे हम चारण या भाटों के मुंह से पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनते हैं। इसकी झलक हमारे नाटकों, लोकनृत्य और लोकगीतों में मिलती है। इस इतिहास में महाराणा प्रताप किताबों के इतिहास से कहीं बड़े नायक हैं। मेवाड़ समेत राजस्थान के घर-घर में पूजे जाने वाले महाराणा प्रताप की वीरता, देशप्रेम और त्याग के ऐसे ही किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में-" महाराणा प्रताप की जीवन-गाथा साहस, शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की प्रतीक है, जिससे देशवासियों को सदा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी।"

मेवाड़ की इस भूमि को कई वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। राणा सांगा, राणा उदय सिंह के वंशज महाराणा प्रताप इन्हीं वीरों में से एक हैं। 9 मई 1540 को चित्तौढ़ नरेश राणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ। उदय सिंह वही, पन्ना धाय द्वारा बचपन में जिनकी जान बचाने का किस्सा आपने किताबों में पढ़ा होगा। राजकुमार होने के बावजूद प्रताप का बचपन भीलों के साथ बीता। 28 फरवरी 1572 को पिता उदय सिंह का निधन हुआ। छोटी रानी के प्रेम के चलते राणा उदय सिंह ने उनके बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि मुगलों के साथ मेवाड़ के सतत संघर्ष को देखते हुए सभी दरबारियों ने प्रताप को गद्दी पर बैठाया। नाराज जगमाल जाकर अकबर से मिल गए। महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि जब तक चित्तौड़ मुगलों से वापस नहीं जीत लेते, सोने की थाली में खाना नहीं खाएंगे, जमीन पर सोएंगे। गद्दी संभालने के बाद अकबर ने उनकी तरफ 4 बार समझौते का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन महाराणा प्रताप ने दासता स्वीकार करने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। इस पर आगे चलकर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। मात्र 3 हजार घुड़सवार और कुछ भील सैनिकों के दम पर महाराणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व वाली अकबर की 10 हजार की फौज को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इसी युद्ध के दौरान उनका प्रिय घोड़ा चेतक घायल हुआ, जिसकी वफादारी की मिसाल आज भी दी जाती है। हल्दी घाटी के 6 साल बाद दीवेर के युद्ध में महाराणा ने मुगलों को हराया। धीरे-धीरे कई इलाके उन्होंने मुगलों से छीन लिए। मातृभूमि के लिए सतत संघर्ष के रास्ते पर वह चलते हुए 19 जनवरी 1597 को चिर निद्रा में लीन हो गए। महाराणा की मौत की खबर जब बादशाह अकबर को दी गई तब वो लाहौर में था। उस समय राजस्थान के एक मशहूर कवि दुरसा आढ़ा भी अकबर के दरबार में मौजूद थे। राणा प्रताप की मौत का समाचार मिलने पर उन्होंने खड़े हो कर पढ़ा -

अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी
गो आडा गवड़ाय जीको बहतो घुरवामी
नवरोजे न गयो न गो आसतां नवल्ली
न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियाण दहल्ली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूंद रसणा डसी
निसा मूक भरिया नैण तो मृत शाह प्रतापसी

यानी तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग़ नहीं लगने दिया, तुमने अपनी पगड़ी कभी नहीं झुकाई। तुमने अपने घोड़े पर शाही मोहर नहीं लगने दी। तुमने कभी शाही झरोखे के नीचे अपनी इल्तजा नहीं की। आज जब तुम्हारी मृत्यु का समाचार दरबार में आया है, देखो बादशाह का सिर झुक गया है। आंख से आंसू बह निकले हैं और उसने अपने दांतों तले अपनी जुबान को ले लिया है। तुम जीत गए प्रताप...

राजस्थान में ये कहानी प्रचलित है कि अकबर ने ये कविता सुनने के बाद दुरसा आढ़ा को इनाम दिया था। शायद यही महाराणा प्रताप की असली जीत थी। ●

पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता

जल संरक्षण वर्तमान समय की एक अहम जरूरत है। इसी तरह अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों से खेती करना भी समय की मांग है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रख कर जहां एक सीआरपीएफ कैंप 'जल संरक्षण' के काम में जुटा है तो वहीं एक किसान ने गुणवत्ता वाले ड्रमस्टिक बीजों से सहजन उगा उदाहरण पेश किया...

सुरक्षा भी, जल संरक्षण भी

जल संरक्षण के लिए 'कैच द रेन' अभियान से प्रेरित होकर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर ने राजस्थान के अजमेर में एक तालाब बनाया है। वर्षा जल संरक्षण का यह काम सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सहगल के नेतृत्व में हो रहा है। सीआरपीएफ कैंप के पास पहाड़ी और जंगल के बीच प्राकृतिक रूप से गहरा एक स्थान था। सीआरपीएफ के जवानों ने उस जगह को और गहरा किया और उसे दो तरफ से घेर दिया। बरसात के समय यह तालाब पानी से लबालब भर जाता है, जिसका इस्तेमाल वन्यजीव, पक्षियों, पेड़-पौधों और सीआरपीएफ कैंप के लिए किया जाता है। साथ ही, पेड़-पौधों की सिंचाई और बागवानी में भी इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। विक्रम सहगल ने बताया कि तालाब में पानी भरने और उसके ओवरफ्लो होने के कारण यहां भूजल स्तर भी ऊपर आ रहा है और इससे यहां के करीब 12 ट्यूबवेल भी रिचार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ ने बारिश का पानी भरने के लिए यहां छोटे-छोटे कई गड्ढे भी बना रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कैच द रेन' अभियान में शामिल होने की अपील पर किए जा रहे इस काम का उद्देश्य जल संरक्षण और पानी को सहेज कर रखना है। ●

सहजन से समृद्ध बन रहा किसान

गुजरात में पाटन जिले के रहने वाले कामराज भाई चौधरी एक ऐसे किसान हैं जो सहजन से समृद्धि की फसल उगा रहे हैं। उन्होंने घर में ही इसके अच्छे बीज विकसित किए और इन बीजों की मदद से जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। वह अपनी उपज तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। वह आगे इसकी खेती बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। चौधरी बताते हैं कि वह 10 साल से इसकी खेती कर रहे हैं और इस खेती का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। उन्हें एक बीघे जमीन से एक लाख से सवा लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इसमें गोबर की खाद ज्यादा डालनी पड़ती है। दरअसल, आयुर्वेद में सहजन की बहुत मांग है। माना जाता है कि सहजन से 300 प्रकार की बीमारी दूर होती है। सहजन को कुछ लोग सर्गवा, मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में अच्छी गुणवत्ता वाले ड्रमस्टिक बीजों को विकसित करने के लिए गुजरात के किसान कामराज चौधरी की सराहना की थी। ●

PMO India
बाबा साहेब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी।

आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है।

DBT के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है: PM @narendramodi

Rajnath Singh
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने कोरोना के खिलाफ जारी राष्ट्रीय अभियान से जुड़े आज चार आग्रह देशवासियों से किए हैं। इस 'टीका उत्सव' से जुड़कर कर हम कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस अभियान के साथ खुद भी जुड़ें एवं औरों को भी जोड़ें।

Amit Shah
कुंभ के लिए @narendramodi जी ने स्वयं संतो से अपील की व संतों ने उनकी अपील को स्वीकार किया। जिसके बाद 13 में से 12 अखाड़ों ने कुंभ का विसर्जन किया व संतों ने जनता को भी कुंभ में न आने की अपील की। मोदी जी की पहल से कुंभ अब प्रतीकात्मक कुंभ में परिवर्तित हो गया,जो बहुत बड़ी बात है।

Nitin Gadkari
#Ramdesivir के प्रोडक्शन को 10 लाख वायल प्रतिमाह बढ़ाने के लिए 7 नए साइट को मंजूरी दी गई है। मैं आदरणीय केंद्रीय उर्वरक राज्यमंत्री श्री @mansukhmandviya जी और प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का धन्यवाद देता हूँ।

Sadananda Gowda
@DVSadanandGowda

In a huge relief to people in this crucial time, after Govt's intervention the price of #Remdesivir is now reduced!
I am grateful to Pharma companies for standing along with PM @narendramodi's fight against #Covid.

Dr. S. Jaishankar @DrSJaish... · 5d
Underlined that in diplomacy today, doing good is being smart. Vaccine Maitri reflects the larger outlook of Vaisudhaiva Kutumbakam.

Health security is now integral to national security. No one is safe till everyone is safe.

8 · 83 · 430

कोरोना से निपटने के लिए दुनिया एक हो जाए : मोदी

वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन से कहा कि भारत सबका मददगार

महामारी ने दिया बदलाव का अवसर

टीका उत्सव मनाओ : मोदी

डिलाई न बरतें, लॉकडाउन की जरूरत नहीं, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का मंत्र

हिंद प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन को और मजबूत करेंगे भारत-फ्रांस

फ्रांस इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में हिस्सा लेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स को तीव्र गश्ती पोत सौंपा

उद्घाटन

आतंकवाद पर नीदरलैंड और भारत का समान रुख : मोदी

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
1-15 मई 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 20 अप्रैल 2021, कुल पृष्ठ-40)

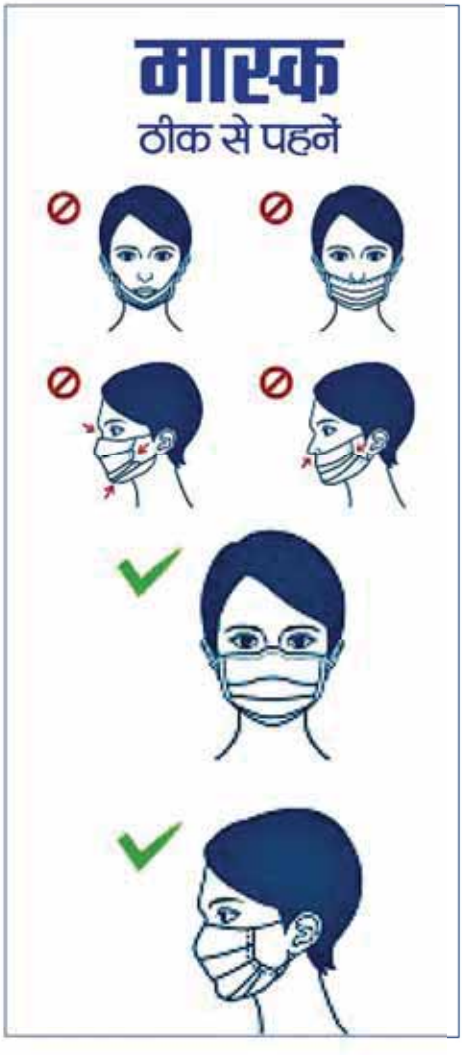

ध्यान दें!
सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें!

वैक्सीनेशन करवाएं • मास्क पहनकर रखें
कोरोना नियमों का पालन करें

सफाई, दवाई और कड़ाई
जीतेंगे कोरोना से लड़ाई

संपादकः
जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रकः
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-
110003 से प्रकाशित

मुद्रणः जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20